



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 585।

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2012/कार्तिक 25, 1934

No. 585।

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2012/KARTIKA 25, 1934

## रक्षोपाय महानिदेशालय

(सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2012

विषय : डायोक्टायल थैलेट (डीओपी) के आयातों के संबंध में सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 11 के अंतर्गत रक्षोपाय जांच-अंतिम निष्कर्ष ।

सा.का.नि. 828(अ).—सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 11 के संबंध में ।

## क. प्रक्रिया

1. सीमा-शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 (जिसे एतदपश्चात् “रक्षोपाय नियम” कहा गया है) के नियम 5 के अंतर्गत (क) केएलजे प्लास्टीसाइजर्स लिमिटेड, (ख) पायल पालीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, (ग) पीसीएल ऑयल एंड साल्वेंट लिमिटेड, और (घ) एन. के. पोलिमर्स एंड एडिटिव्ज मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी ने यह आरोप लगाते हुए कि डायोक्टायल थैलेट के बढ़ते हुए आयातों से भारत में डायोक्टायल थैलेट के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हो रही है और/या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो रही है, डायोक्टायल थैलेट के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की मांग करते हुए एक आवेदन पत्र दायर किया है । भारत में डायोक्टायल थैलेट के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच प्रारंभ करने का नोटिस 23 मई, 2012 को जारी किया गया था और सा.का.नि. 383(अ) के तहत उसी दिन भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था ।

2. दिनांक 23 मई, 2012 के जांच शुरुआत के नोटिस की एक प्रति तथा घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति केन्द्रीय सरकार वाणिज्य मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों, निर्यातक देशों की सरकारों को नई दिल्ली स्थित उनके राजदूतावासों/ उच्चायोगों के जरिए तथा अधोलिखित सभी जात हितबद्ध पक्षकारों को सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6(2) और 6(3) के अनुसार भेज दी गई थी।

### घरेलू उत्पादक

- (क) केएलजे प्लास्टीसाइजर्स लिमिटेड
- (ख) पायल पालीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
- (ग) पीसीएल ऑयल एंड साल्वेंट लिमिटेड
- (घ) एन.के.पोलिमर्स एंड एडिटिव्ज मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी

### आयातक/ प्रयोक्ता

- क. अल्फा पोलिमर्स, अल्फा नगर, नगर माला, आदिवरम एक अल्गापुरम- 636 016
- ख. अनुकम्पा पोलिमर्स एंड टेक्नालोजीज प्राइवेट लिमिटेड, बी-21 औद्योगिक एस्टेट, सनतनगर, हैदराबाद -500018, आ.प्र.
- ग. ग्लोस्टर केबल्स लिमिटेड, 310/ ई, एनएच-7, कल्लाकल गांव, तुप्राणमंडल मेढक जिला आंध्र प्रदेश
- घ. प्राइम पोलिमर्स, संख्या-18, लाल बाग रोड, बंगलोर-560027, कर्नाटक
- ड. एस. गोपाल कामर्थ (कोचीन) संख्या 39/330ए, अरंगत रोड, पी बाक्स नं.2021 ऐरनाकुलम, कोचीन- 682018
- घ. क्वायर टफ्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नं. 49(साइट -ए), रबर पार्क, इरापुरम गांव, कन्नायुनाडु तालुक, पेरुम्बावूर।
- छ. केराफाइवरटेक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नं.53-57, किन्नरा (ईपीआईपी) कुसुमागिरी, कक्कनाड, केरल
- ज. दि एलेप्पी कम्पनी, 14/385ए पुथाननगढ़ी, मुहाम्मा 688525, केरल
- झ. केरल बेलर्स (प्रा.) लिमिटेड ए.एस.रोड, लेप्पी, एलेप्पी 688007, केरल
- ज. ट्यूब प्रोडक्ट्स महादेवपुरा, हवाइट फिल्ड रोड, बंगलोर 560048, कर्नाटक
- ट. जी टी (इंडिया) अहमदाबाद, भारत सीमेंट पाइप कम्पाउंड नरोल सर्कल, नरोल, अहमदाबाद, 382405, गुजरात

ठ. निशान मार्किटिंग, बी-204 कृष्णा काप्लेक्स, राजपथ क्लब के मसाने, आफ एस जी रोड, अहमदाबाद- 380054, गुजरात

ड. सिंगमा आर्गनिक्स एंड कैमिकल्स प्रा. लिमिटेड सज्जन हाउस, 7 न्यू अग्रवाल नगर, लोटस नवलखा के सामने, इंदौर-452001

ढ. लेजर केबल्स प्रा. लि. पी ओ विप्रन्नापाड़ा जालान इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स, जंगपुर हावड़ा 711411, पश्चिम बंगाल

ण. प्लास्टी पैक, 115 कालेज स्ट्रीट, यूनिट-3 ई, तृतीय तल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

त. जैन कैमिकल (जयपुर) एफ-542 रोड सं.1, डीवी के आई एरिया जयपुर 302004, राजस्थान

थ. जैन कैमिकल एंड प्लास्टिक (दिल्ली) 3545/5 जयमाता मार्किट, त्रि नगर, नई दिल्ली- 110035

द. लिओ विनायल्स, कपूरथला रोड, जलंधर, पंजाब

ध. जैन को इंटरव्यू प्राइजेज, जैन बिल्डिंग, बस्ती बावा खेल कपूरथला रोड, जलंधर-144021 पंजाब

न. आरविन्द प्लास्टिक उद्योग, ए-55 गिरिराज इंडस्ट्रियल एस्टेट, महाकाली केब्स रोड, अंधेरी (पूर्व) मुम्बई

प. राधा प्लास्टिक इंडस्ट्रीज (दमण) 48/2, दमण इंडस्ट्रियल एस्टेट, कदैया नानी दमण

फ. वरुण आर्गनिक्स प्रा. लिमिटेड- 101, सुजाता चैम्बर, 1/3, ए बी गांधी मार्ग मस्जिद बंदर, मुम्बई- 400009

ब. कृष्णा इंटरप्राइजेज, शाप नं. 3, कमल मोहन हाउसिंग सोसायटी, 126 नाना पेठ, पुणे-411002

भ. ए.डी इंडस्ट्रीज, बी-4 गिरिराज एस्टेट, महाकाली केब्स रोड, अंधेरी (पूर्व) मुम्बई

म. डायमंड पाइप्स एंड ट्यूब्स प्रा. लिमि. सं. 50 7वां क्रास, विल्सन गार्डन, बंगलौर-560027 कर्नाटक

य. बीडीएस इंडस्ट्रीज, सर्वे 70/2(बी) दमण इंडस्ट्रियल एस्टेट, कदैया, दमण कक्क. पूनम इंटरनेशनल 195/2, चिकन हल्ली रोड, बोम्माना हल्ली, बंगलौर-560068

ख. रायल कुशन विनायल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, प्लाट नं. 55, ग्राम गरधिया, तालुक, सायली जिला बडौदा, गुजरात

गग. विनायल रायल प्लास्टीकोट्स लिमिटेड, प्लाट सं. 319 बडौदा गोधरा रोड, बासका विलेज हलोल, पंचमहल

निर्यातक

क. मै. बीएएसएफ पैट्रोनास कैमिकल्स, एसडीएम बीडीसी 802, सेंट्रल टावर, विस्मा कान्सपन्त 1 जालान एसएस 16/4, सुबंग जाया-47500 मलेशिया

ख. कैमक्रास इंक, आइसा, योगसेई बिल्डिंग 4था तल नामदेउन रोड, 5-केस, चुंग-कु. सियोल, दक्षिण कोरिया

ग. हुमाडे कारपोरेशन, कमरा नं. 1505 मास्टर टावर, बी/डी 553, डोहा डांग, मापो गु, सियोल 121-748, दक्षिण कोरिया

घ. मै. वूरी एंड कारपोरेशन, कमरा 905, ओलम्पिया बिल्डिंग सं. 196, जमसिल्ब आन डोर्ग सोगर्पांगु सियोल, दक्षिण कोरिया

ड. दि नारमंडी ग्रुप, एस.ए, टेम्पल फाइनेन्सियल सेंटर पी ओ बाक्स 228, लीवार्ड हाईवे, प्रोविडेन्सियल्स, तुर्कस एंड काकोस आईलैंड्स, ब्रिटिश वेस्ट इंडीज, नीदरलैंड्स

च. गल्फ रिसोर्सेस डिवलपमेंट कारपोरेशन पी ओ बाक्स 61283 जबेल अली, दुबई, यूएई

छ. पैट्रोकेम मिडिल ईस्ट एफ जेडई, पी.ओ. बाक्स 17028 जबेल अली दुबई- यूएई

ज. के ए एस बी पैट्रोलियम एफ जेड कम्पनी पी ओ बाक्स 117280, दुबई यूएई

झ. यू पी सी टेक्नालोजी कारपोरेशन 5एफ, 20 लेन 478 रुडगुआंग रोड, नीहू चिउ, ताइपेई ताईवान

ज. कान्टीनेन्टल कैमिकल कारपोरेशन, पीटीई लिमिटेड 2 सिराया प्लाजा, जुरांग आईलैण्ड, सिंगापुर-6277857

ट. डिनोविक पीटीसी लिमिटेड 5 शेन्टन वे 19-08 यू आई सी बिल्डिंग, सिंगापुर-068808

ठ. नीमर कैमिकल्स पाकिस्तान लिमिटेड 51-एन इंडस्ट्रियल एरिया, गुलमर्ग-II, लाहौर, पाकिस्तान

ड. आईसीसी कैमिकल कारपोरेशन 460 पार्क एवेन्यू, न्यू यार्क, यूएसए

ढ. विन्मार ओवरसीज लिमिटेड 16800 इम्पीरियल वैली ड्राइव सूट 499 हाउसटन, टीर्क्स 77060

न. एवरेस्ट पालीमर्स प्रा. लिमिटेड पी.ओ. बाक्स सं.47 मकवानपुर, नेपाल

त. फराबी पैट्रोकैमिकल्स कं. सं. 35/2, नार्थ गाड़ी एवेन्यू, सनई अलेय, तेहरान-ईरान

### निर्यातक राष्ट

क. कोरिया गणराज्य अपने राजदूतावास, नई दिल्ली के जरिए

ख. ताईवान, अपने राजदूतावास, नई दिल्ली के जरिए

ग. मलेशिया नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग के जरिए

[भाग II-खण्ड 3(i)]

3. सभी जात घरेलू उत्पादकों और आयातकों तथा निर्यातकों को भी उसी दिन प्रश्नावलियां भेजी गई और उनसे कहा गया कि वे अपने प्रत्युत्तर 30 दिन के अंदर प्रस्तुत कर दें।

4. निम्नलिखित पक्षकारों से यह अनुरोध प्राप्त हुआ कि उन्हें हितबद्ध पक्षकार माना जाए तथा समय विस्तार कर दिया जाए। निर्धारित अवधि के अंदर जांच पूरी करने की समय सीमा पर विचार करते हुए रक्षोपाय नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार उत्तर समय सीमा पर विचार करते हुए रक्षोपाय नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार उत्तर प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था, कर दिया गया।

### निर्यातक

- मै. एल जी कैम लिमिटेड कोरिया अपने अधिवक्ता मै. डब्ल्यूटीसी कन्सलटेन्ट्स के जरिए
- मै. नान या प्लास्टिक्स कारपोरेशन, ताईवान

### उपभोक्ता

- लेदर क्लाथ एंड प्लास्टिक्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली

5. मैक्सिको की सरकार ने अपने राजदूतावास के जरिए, मैसर्स जी टी इंडिया और मैसर्स निशान मार्केटिंग ने अनुरोध किया कि उनका नाम हितबद्ध पक्षकारों की सूची से हटा दिया जाए क्योंकि वे डायोकटायल थैलेट (डीओपी) का निर्यात/ आयात नहीं कर रहे हैं। इन अनुरोधों पर सहमति दे दी गई।

6. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी का घरेलू उत्पादकों के संयंत्रों का स्थल दौरा करके जरूरी समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया। सत्यापन रिपोर्ट के अगोपनीय पाठ को सार्वजनिक फाइल में रखा गया।

7. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त किये गये सभी विचारों को समुचित निर्धारण करते समय ध्यान में रखा गया। प्राप्त या अधिग्रहीत अगोपनीय सूचना सार्वजनिक फाइल में रखी गई।

8. 25 सितम्बर, 2012 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया गया जिसके लिए नोटिस 20 सितम्बर, 2012 को भेजा गया था। इस सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाले नोटिस 20 सितम्बर, 2012 को भेजा गया था। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे भौखिक रूप से व्यक्त अपने विचारों को सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे भौखिक रूप से व्यक्त अपने विचारों को सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के उप-नियम (6) के अनुसार 1 अक्टूबर, 2012 तक लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतिकरण की प्रति सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई। हितबद्ध पक्षकारों को, अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिखित प्रस्तुतिकरणों

का 4 अक्टूबर, 2012 तक प्रति-प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, दायर करने का अवसर भी प्रदान किया गया। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत या प्रति-प्रत्युत्तर के रूप में अभिव्यक्त सभी विचारों की जांच की गई तथा समुचित निर्धारण करते समय उन्हें ध्यान में रखा गया है। ताइवान की सरकार और कोरिया गणराज्य की सरकार ने सुनवाई के पश्चात क्रमशः दिनांक 25.9.2012 और 1.10.2012 को ई-मेल के जरिए अपने प्रस्तुतिकरण लिखित रूप में भेजे, परन्तु उनकी प्रतियां दायर नहीं की गई। एलसीपीएमए ने भी सुनवाई पश्चात लिखित प्रस्तुतिकरण दिनांक 5.10.2012 को हार्ड कॉपी में प्रस्तुत किया। इसीतरह, एलसीपीएमए ने सुनवाई पश्चात प्रति-प्रत्युत्तर की हार्ड कॉपी दिनांक 5.10.2012 को प्रस्तुत की। तथापि, सक्षम प्राधिकारी इन सभी प्रकार्यात्मक चूकों/ विलम्ब पर विचार किया गया और उन्हें माफ कर दिया गया।

9. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा और अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा लिखित प्रस्तुतिकरणों या प्रति-प्रत्युत्तरों में अभिव्यक्त विचारों और घरेलू उद्योग के उत्तर प्रस्तुतिकरणों की जांच की गई और समुचित निर्णय लेते समय उनको ध्यान में रखा गया है।

#### ख. घरेलू उद्योग के विचार

क. याचिकाकर्ता सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुरूप घरेलू उद्योग बनते हैं क्योंकि डीओपी के कुल भारतीय उत्पादन में उनका प्रमुख अनुपात है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है:

क्र.सं.	वर्ष	याचिकाकर्ता (%)	अन्य भारतीय उत्पादक (%)	सभी भारतीय उत्पादक (%)
1	2009-10	94	6	100
2	2010-11	91	9	100
3	2011-12	91	9	100

ख. वर्ष 2008-09 की सूचना को इस अवधि में मंदी के मद्दे नजर नकार दिया गया। अन्यथा, वर्ष 2008-09 से आंकड़ों का विश्लेषण करते समय यह ध्यान में रखना अपेक्षित माना गया कि वर्ष 2008-09 वह अवधि थी जब घरेलू उद्योग मंदी से पीड़ित था और इसलिए यदि उत्तरवर्ती वर्षों से तुलना की जाए तो सभी पैरामीटर सुधार प्रदर्शित करेंगे।

ग. रक्षोपाय नियम और अर्जीना फुटवियर मामले तथा यूएस लाइन पाइप मामले में निर्णय के आशय के अंतर्गत आयातों में अचानक, तीव्र और अत्यधिक वृद्धि हुई।

घ. संपूर्ण अवधि तथा हाल की अवधि में उत्पादन एवं खपत की तुलना में आयातों में वृद्धि हुई।

ड. आयातों में यह वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हुई:

- i. चीन के उत्पादकों द्वारा थैलिक एनहाइड्राइड के नये संयंत्रों की स्थापना और उसके परिणामस्वरूप तृतीय देशों में थैलिक एनहाइड्राइड की बेशी क्षमता से थैलिक एनहाइड्राइड के उत्पादन का डीओपी के उत्पादन में विपर्यय हुआ।
- ii. चीन में थैलिक एनहाइड्राइड की घटती मांग के कारण थैलिक एनहाइड्राइड के उत्पादन का डीओपी के उत्पादन में विपर्यय हुआ।
- iii. यूरोप एवं अमेरिका की बाजारों में मंदी।
- iv. यूरोप में डीओपी के प्रयोग पर प्रतिबंध
- v. विचाराधीन उत्पाद की भारत में बढ़ती मांग

उपर्युक्त तथ्यों के कारण कोरिया और ताइवान के नियातकों को अपने उत्पाद के लिए विकसित बाजार तलाश करने को मजबूर होना पड़ा और भारत अत्यधिक सुलभ पसंद होने के कारण, इसे अपना लक्ष्य बनाया गया जिससे भारत में आयातों में वृद्धि हुई।

च. संवर्धित आयातों ने घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग पर विपरीत प्रभाव डाला है।

छ. घरेलू उद्योग की बिक्री में वर्ष 2010-11 तक वृद्धि हुई परन्तु अभी हाल ही की अवधि के दौरान इसमें गिरावट आयी जबकि आयातों में वृद्धि हुई है।

ज. घरेलू उद्योग बाजार हिस्से में गिरावट के कारण मालसूची एकत्र होने की समस्या का सामना कर रहा है जिससे उसका उत्पादन एवं क्षमता उपयोग प्रभावित हुआ।

झ. बाजार में अपनी मौजूदगी बनाये रखने के लिए घरेलू उद्योग को बिक्री लागत की तुलना में अपनी कीमतें बहुत कम करनी पड़ी जिससे उनको अत्यधिक घाटा हुआ। साथ ही, अभी हाल ही अवधि में लाभप्रदायकता और उसके परिणामस्वरूप नगद लाभ तथा निवेश पर अर्जन में गिरावट आनी शुरू हो गई जिसमें पहले वास्तव में सुधार हुआ था।

ज. गंभीर क्षति की चुनौती निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होती है।

- i. घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच कीमतों में बहुत अधिक अंतर है;
- ii. विदेशी उत्पादकों के पास अत्यधिक अप्रयुक्त क्षमताएं हैं। परिणामस्वरूप, विदेशी उत्पादक यथासंभव सीमा तक अतिरिक्त बाजारों की तलाश कर रहे हैं;

- iii. कोरिया और ताइवान के निर्यातोन्मुखी उत्पादों के लिए चीन की प्रमुख बाजार अवरुद्ध हो गये जबकि भारतीय बाजार काफी मजबूत है;
- iv. यूरोप में डीओपी का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगे हुए थे जो यूरोप में संकट के कारण और अधिक खराब हो गये। इन प्रतिबंधों के कारण उत्पादकों/निर्यातकों ने अपने उत्पादों के लिए नये बाजारों की तलाश करना शुरू कर दिया और भारत, अपनी मांग के कारण ने उनके लिए बेहतर अवसर प्रदान किये जिससे इन देशों से आयातों में वृद्धि हुई और आयातों में और अधिक वृद्धि होने का खतरा है।

ट. संभावित लक्षित उत्पाद पर नगण्य प्रभाव पड़ा है और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि घरेलू उचोग की रक्षा करना अनिवार्य है, इसलिए रक्षोपाय का अधिरोपण जन हित में होगा।

#### ग. निर्यातक राष्ट्रों के विचार

##### कोरिया की सरकार

क. वर्ष 2011-12 के आंकड़ों का वर्णन वार्षिकीकृत रूप में किया गया जिससे अत्यधिक मिथ्या निरूपण हुआ है। इसे इस तथ्य से देखा जा सकता है कि कोरिया के निर्यात वर्ष 2011 की पहली तिमाही में 11924 मी.टन थे जो वर्ष 2012 की पहली तिमाही में घटकर 3382 मी.टन. रह गये।

ख. आयातों की यात्रा में 2008-09 से 2009-10 तक तीव्र गिरावट आई, वर्ष 2010-11 में कुछ वृद्धि हुई और 2011-12 के आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं। अतः याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि आयातों में अचानक, तीव्र एवं अत्यधिक वृद्धि हुई, डाटा द्वारा प्रमाणीकृत नहीं होता है।

ग. कोई अप्रत्यासित परिस्थितियां भी प्रदर्शित नहीं हुई क्योंकि कोरिया ने यूरोप को मुश्किल से कभी कोई निर्यात किया होगा और इसलिए यूरोप के संकट में भारत के निर्यातों पर शायद ही कोई प्रभाव डाला हो।

घ. उत्पादन क्षमता और क्षमता निर्माण सभी में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है और इस कारण घरेलू उचोग को कोई क्षति नहीं हुई। घरेलू उचोग की प्रवृत्तियां भी रक्षोपाय करार के अनुच्छेद-4 में यथा वर्णित 'गंभीर क्षति' का कोई चिन्ह प्रदर्शित नहीं करती हैं।

ड. घरेलू उचोग को कथित क्षति थैलिक एनहाइड्राइड पर रक्षोपाय शुल्क लगाने से हुई है और अतः, कोई कारणात्मक संबंध भी नहीं है।

##### ताइवान की सरकार

[भाग II—खण्ड 3(i)]

क. भारत में डीओपी की स्थानीय आपूर्ति में कमी होने के कारण ताईवान के एक नियातक को वर्ष 2010-11 में भारतीय ग्राहकों से कई आर्डर मिले थे। इस अवधि के पश्चात भारत को नियात में कमी आई।

ख. भारत में डी ओ पी की घरेलू मांग उत्पादन से अधिक हो गई और इस प्रकार डीओपी के आयात, भारतीय खपत की जरूरत पूरी करने के लिए किए गए थे।

#### घ. आयातकों/उपयोक्ताओं के विचार

##### चमड़े का कपड़ा तथा प्लास्टिक विनिर्माण एसोसिएशन

क. यह शुरुआत अयथार्थ आंकड़ों पर की गई और अतः यह जांच शुरुआत प्रारंभ से ही गलत है जैसा कि आईसीआई इंडिया लिमिटेड बनाम कमिश्नर आफ कस्टम कलकत्ता 2003 (151) ई एल टी 336 (ट्र-डेल) के मामले में धारित किया गया है।

ख. घरेलू उद्योग का तुलनपत्र क्षति प्रदर्शित नहीं करता है घरेलू उद्योग संबंध वस्तु का उत्पादन और व्यापार दोनों करता है। अतः, संवर्धित आयातों से घरेलू उद्योग को भी लाभ हुआ है।

ग. आयात में वृद्धि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों के कारण हुई और फिर घरेलू उद्योग द्वारा आयातों की सूचना को घरेलू उद्योग ने छुपाया है।

घ. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता क्षमता उपयोग और बिक्री में वृद्धि है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की बेसी क्षमता उसकी मांग के अनुरूप नहीं है और इसलिए आयातों से घरेलू उद्योग का कोई क्षति नहीं हो रही है।

ड. घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति घरेलू उद्योग के न्यून क्षमता उपयोग के कारण हुई जो घरेलू उद्योग की अत्यधिक विनिर्मित क्षमता और आयातों के कारण हुई।

च. डी ओ पी का बड़ा प्रयोक्ता होने के कारण, इसके सदस्य, रक्षोपाय शुल्क लगाने के मामले में अधिक प्रभावित पक्षकार होगे क्योंकि इसके सदस्यों के उत्पाद को कोई संरक्षण नहीं मिलता है।

छ. इसलिए रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण, यदि यह जनहित में नहीं है तो, नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भारतीय खाद्य निगम बनाम कामधेनु पशु आहार उद्योग (1992, इंडला एस सी 426), राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम बनाम एस. रघुनाथन एवं अन्य, 1998 (7) में रिपोर्ट एस सी सी 66, श्वेत/ पीत फासफोरस पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए 1999 में यूनाइटेड फासफोरस, यूनाइटेड फासफोरस बनाम महानिदेशक (रक्षोपाय) 2000 (118) ई एल टी 326 (दिल्ली), फासफोरस लिमिटेड बनाम महानिदेशक (रक्षोपाय) 2000 (118) ई एल टी 310 (एस सी) धारित किया है।

ज. कोई ऐसी अप्रत्यासित घटना भी नहीं है जिससे रक्षोपाय शुल्क जरुरी हो गया हो और, इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की कोई समायोजन योजना भी नहीं है।

ड. घरेलू उद्योग द्वारा प्रति प्रत्युत्तर

चमड़े के कपड़े तथा प्लास्टिक मैन्यूफॉर्मर्स एसोसिएशन द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के संबंध में

क. रक्षोपाय जांच पूर्णतया पृथक आधार पर है और इसमें बहु-स्तरीय प्रक्रिया शामिल है जिसमें अलग-अलग पक्षकारों से सूचना मिलानी अपेक्षित होती है। महानिदेशक को जांच शुरू करना अपेक्षित होता है, न कि जांच शुरुआत के लिए जांच करना।

ख. याचिकाकर्ता कम्पनियां कई अन्य तरह के प्लास्टी साइजर्स का निर्माण कर रही हैं तथा अन्य व्यापारिक गतिविधियों में भी संलिप्त हैं। अतः, याचिकाकर्ता कम्पनियों के तुलनपत्र वर्तमान प्रयोजन के लिए संगत नहीं हैं।

ग. याचिकाकर्ताओं में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयात को छिपाया नहीं है बल्कि उन्होंने अपनी याचिका में इसका उल्लेख कर दिया है। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ताओं का यह विवाद है कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों का अपवर्णन कर दिया जाना चाहिए।

घ. यदि 2009-09 से 2010-11 के आंकड़ों की तुलना की जाए तो उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग में वृद्धि प्रदर्शित होती है। यह पहले ही निवेदन कर दिया गया है कि 2008-09 मंदी के कारण एक असामान्य अवधि है और शिरा-दर शिरा आधार पर तुलना करना, उचित तुलना नहीं है।

ड. लाभ में दावाकृत कमी न्यून क्षमता उपयोग के कारण नहीं हुई। वास्तव में, घरेलू उद्योग ने क्षमता का उपयोग, कुछ हद तक अन्य प्रकार के प्लास्टीसाइजर्स का उत्पादन करके किया गया है।

च. यह नोट किया जाना चाहिए कि यद्यपि डायोक्टाइल थैलेट के अधिकांश उत्पादक इस जांच में भाग ले रहे हैं तथा उपभोक्ता एसोसिएशन के केवल एक प्रतिनिधि ने इस रक्षोपाय जांच में प्रतिभागिता की है। केवल यह ही दर्शाता है कि प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क का संभावित विपरीत प्रभाव अल्पतम होगा। इसकी अवलेहनना नहीं की जा सकती है कि यदि प्रभाव अधिक होता तो भारी संख्या में उपभोक्ताओं ने अपनी चिंता व्यक्त की होती। तथापि, ऐसा नहीं हुआ।

छ. यह कई घटनाओं का संगम हो सकता है जो अप्रत्याशित विकास के आधार के रूप में जोड़ी जा सकती हैं। याचिकाकर्ताओं ने कई घटनाओं के उदाहरण दिए हैं जो उस अप्रत्याशित

विकास का भाग बनती हैं जिससे भारत, में डायोक्टाइल थैलेट के आयातों में वृद्धि हुई। ये सभी विकास अप्रत्याशित थे और वे स्पष्टतः 'अप्रत्याशित विकास' बनते हैं। ज. यह जरूरी नहीं है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित या निवेशित समायोजन योजना को रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से पहले ही परिणाम प्रदर्शित करना शुरू कर देना रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराए गए/योजनाकृत सकारात्मक समायोजन योजना को सुकर बनाने के लिए किया जाता है।

कोरिया की सरकार द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के संबंध में  
क. वर्ष 2011-12 की संपूर्ण अवधि के लिए प्रदान कराए गए वास्तविक डाटा की तुलना, पहले उपलब्ध कराए गए वार्षिकीकृत डाटा से करने पर यह दर्शाता है कि वार्षिकीकृत आंकड़ों तथा वास्तविक आंकड़ों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

ख. यह पुनः उल्लेख किया जाता है कि डायोक्टाइल थैलेट के आयातों में वृद्धि समग्र रूप से तथा उत्पादन एवं खपत के संबंध में भी हुई है।

ग. आयातों में किसी एक देश का मूवमेंट रक्षोपाय जांच के अंतर्गत पूर्णतया असंगत है।  
घ. यूरोप में प्रासंगित अन्तोपद की मांग में गिरावट और चीन में अत्यधिक क्षमता वृद्धि (थैलिक एनहाइड्राइड और डीओपी के लिए) के परिणामस्वरूप चीन के विनिर्माताओं द्वारा डीओपी के अधिप्रापण में तीव्र गिरावट आई।

ड. घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन थैलिक एनहाइड्राइड पर रक्षोपाय शुल्क का कोई संबंध नहीं है।

च. आयातकों/ प्रयोक्ता उद्योग द्वारा प्रति-प्रत्युत्तर

#### चमड़े के वस्त्र तथा प्लास्टिक विनिर्माण एसोसिएशन

क. निर्यातकों के भारतीय बाजार में पण बहुत कम है और इस कारण उन्होंने भाग नहीं लिया है। भाग न लेने का आशय यह नहीं है कि वे इस मामले में समर्थक नहीं हैं।

ख. एलसीपीएमए अत्यधिक प्रभावित होगी और वह इसमें प्रारंभ से ही भाग ले रहा है अतः इस संबंध में कोई भी आपति नहीं उठायी जा सकती है।

ग. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों का महानिदेशक द्वारा सत्यापन किया जाना है क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों ने कुछ आपत्तियां की हैं और प्रमाण का दायित्व घरेलू उद्योग पर है।  
घ. घरेलू उद्योग ने लेने देनवार-आयात आंकड़े नहीं दर्शाए हैं जिससे यह प्रदर्शित होता है कि आयात घरेलू उद्योग और घरेलू उद्योग के हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए।

ड. नवीन आंकड़ों का परिचालन नहीं किया गया है जैसा कि घरेलू उद्योग ने दावा किया है और वर्ष 2008-09 के आंकड़ों की अवहेलना करने के संबंध में की गई ट्ली को अनुमति

नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह विधि विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, कारबन ब्लैक, 1998 के मामले में, जांच शुरुआत के बाद के आकड़ों को रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है।

च. आयातों में वृद्धि घरेलू उद्योग द्वारा आयातों के कारण हुई है।

छ. घरेलू उद्योग को कोई भी क्षति नहीं हुई है, वास्तव में तो घरेलू उद्योग को उनके द्वारा किए गए आयात के कारण लाभ हुआ है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की कोई चुनौती भी नहीं है।

ज. कारणात्मक संबंध भी मौजूद नहीं हैं क्योंकि आयात घरेलू उद्योग द्वारा किए गए हैं और उन्हें आयातों से लाभ हुआ है।

झ. यह शुल्क जनहित के विरुद्ध होगा क्योंकि बाजार में पहले से ही स्फीति की प्रवृत्ति है। घरेलू उद्योग द्वारा दिखाया गया परिकलन बिना किसी तर्कसंगत आधार का है।

ज. घरेलू उद्योग की कोई भरोसेमंद समायोजन योजना नहीं है।

### महानिदेशक के निष्कर्ष

1. मैंने मामले के रिकार्ड घरेलू उद्योग, प्रयोक्ता आयातकों एवं निर्यातक राष्ट्रों द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तरों की सावधानी पूर्वक जांच की है। विभिन्न पक्षकाकर्तों द्वारा की गई प्रस्तुतियों और उनसे तीसरे मुद्दे का अधोलिखित निष्कर्ष में उपयुक्त स्थान पर समुचित निपटान किया गया है।

2. सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख में भारत में गैर-विभेदकारी आधार पर किए गए आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने का उल्लेख है। धारा 8ख (1) में किसी ऐसी वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने का प्रावधान है जिसका भारत में इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों के अधीन आयात किया जा रहा है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो रही हो।

3. सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 में जांच को शासित करने वाले ढंग एवं सिद्धांतों का प्रावधान है।

4. तदनुसार, उक्त नियमों के अनुसार जांच की गई और इस अधिसूचना के जरिए अंतिम निष्कर्ष दर्ज किया गया।

### क. विचाराधीन उत्पाद

5. विचाराधीन उत्पाद डायोक्टायल थैलेट (एक कार्बनिक यौगिक) है और इसका संक्षिप्त नाम 'डीओपी' है। इसे बीआईएस (2-इथायलहेक्साइल) थैलेट के रूप में भी जाना जाता है, इसका सामान्य संक्षिप्तीकरण डीईएचपी है। यह उत्पाद रंगहीन विस्कोस तरल, तेल में घुलनशील, परन्तु पानी में अधुलनशील है। इसमें अच्छे प्लास्टीसाइजिंग गुणधर्म होते हैं। कई

कम्पनियों द्वारा इसका भारी पैमाने पर उत्पादन किए जाने के कारण इसके कई नाम एवं परिवर्णी शब्द हो गए हैं जिसमें बीईएचपी और डाय-2 इथायल हेकजायल थैलेट भी शामिल हैं। यह पीवीसी से बनी वस्तुओं का विनिर्माण करने में प्लास्टीसाइजर के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक में 1% से 40% तक डीईएच पी होती है। इसे कैपेसिटर्स में हाइड्रलिक तरल एवं डायइलेक्ट्रिक तरल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है डीईएचपी का प्रयोग ग्लो स्टिक्स में भी किया जाता है क्योंकि इसके उपयुक्त गुणधर्म और न्यून लागत होती है। इसका प्रयोग इन्ट्रावीनस ट्यूबिंग एवं बैग्स, कैथेटर्स, नेसो गैस्ट्रिक ट्यूब्स, डायलासिस बैग्स एवं ट्यूबिंग तथा ब्लड बैग्स ट्रांसक्यूजन ट्यूबिंग तथा एअर ट्यूब्स जैसे चिकित्सा उपकरणों में प्लास्टी साइजर के रूप में भी किया जाता है।

6. डायोक्टायल थैलेट को सीमा शुल्क टैरिफ अधिसूचना, 1975 के अंतर्गत सीमा शुल्क उपशीर्षक सं. 29173920 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

7. विचाराधीन उत्पाद डायोक्टायल थैलेट (एक कार्बनिक यौगिक) है और इसका संक्षिप्त नाम 'डीओपी' है। इसे बी आई एस (2-इथायलहेक्साइल) थैलेट (2-इथायलहेक्साइल) के रूप में भी जाना जाता है। सामान्यतः इसका संक्षिप्त नाम 'डीईएचपी', एक कार्बनिक यौगिक भी है के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है।

8. यह, घरेलू रूप से उत्पादित डायोक्टायल थैलेट आयातित डायोक्टायल थैलेट के सभी संबंधीय में समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पाद की परिधि के अंतर्गत आता है और यह कि घरेलू रूप से उत्पादित डायोक्टायल थैलेट रक्षोपाय शुल्क नियमावली, 1997 के नियम 2 (ड.) के आशय के अंतर्गत आयातित डायोक्टायल थैलेट के समान मद है।

#### ख. घरेलू उत्पाद

9. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8(ख) में निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है:

"घरेलू उत्पाद का आशय उन उत्पादकों से है जो-

- (i) समान मद या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी मद का भारत में समग्र उत्पादन करते हैं;
- (ii) समान मद या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी मद का भारत में समग्र आउटपुट का भारत में उक्त मद के कुल उत्पादन में प्रमुख हिस्सा है।

10. डायोक्टाइल थैलेट (डीओपी) के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए यह आवेदनपत्र मै. के.एल जे प्लास्टी साइजर्स लिमिटेड रिलवासा, मै. एन केपालीयर्स एंड एडिरिब्ज मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, दमन, मै. पायल पालीप्लास्ट लिमिटेड, दमण और मैसर्स पी सी एल अयल एंड सालवेट लिमिटेड दमण, द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया

गया है। आवेदकों का अभिज्ञान किया है अर्थात् मैं रचना प्लास्टी साइजर्स एंड मैं ललिता कैम इंडस्ट्रीज प्रा. लि। तथापि आवेदकों ने बताया कि मैं ललित कैम इंडस्ट्रीज प्रा. लि। अब बंद हो चुका है। आवेदकों ने अपने को इस आधार पर प्रमुख उत्पादक सिद्ध किया है कि उनका उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का लगभग 98% बनता है। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना देश में समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु के उत्पादन की निम्नलिखित दर्शायी गई है-

विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आवेदक	मी.टन	60,242	69,468	77492	74943
अन्य भारतीय उत्पादक	मी.टन	3515	4753	7218	1878
कुल भारतीय उत्पादक	मी.टन	63,757	74,221	84,710	76,821
आवेदकों का हिस्सा	%	94%	94%	91%	98%

11. इसके अतिरिक्त हितबद्ध पक्षकरों द्वारा आवेदकों को घरेलू उयोग के रूप में मानने के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया गया। अतः, यह धारित किया जाता है कि चार आवेदक घरेलू उत्पादक रक्षोपाय शुल्क नियमावली, 1997 की धारा 8ख(6)(ख)(iii) के आशय के अंतर्गत घरेलू उत्पाद बनते हैं और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं।

#### ग. जांच अवधि (पीओआई):

12. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 रक्षोपाय संबंधी करार एवं जीएटीटी के संगत अनुच्छेद XIX विशेष रूप से यह परिभाषित नहीं करते हैं कि जांच अवधि क्या होनी चाहिए। रक्षोपाय साधनों संबंधी विभिन्न वाद विधियों से यह स्पष्ट है कि न तो रक्षोपाय संबंधी घरेलू कानून और न ही रक्षोपाय संबंधी करार एवं जीएटीटी के अनुच्छेद XIX में जांच अवधि के संबंध में विशिष्ट दिशा निर्देश नहीं हैं, सिवाय इस तथ्य के कि संगत जांच अवधि पर्याप्त रूप से लम्बी हो जिससे संवर्धित आयातों एवं गंभीर क्षति के संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सके।

13. आवेदकों ने वर्तमान मामले में यह तर्क देते हुए 2009-10 से 2011-12 (सितम्बर, 2011 तक) की अवधि के आयात एवं क्षति आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि वर्ष 2008-09 को नकार दिया जाना चाहिए और मौजूदा जांच के लिए वर्ष 2009-10 से तथा उसके बाद की सूचना पर विचार करना चाहिए क्योंकि वर्ष 2008-09 एक असामान्य अवधि थी जहां घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर न केवल विचाराधीन उत्पाद के उद्योगों, बल्कि भारी संख्या में अन्य सेक्टरों को वैश्विक मंडी के कारण-नुकसान हुआ। निदेशालय ने वर्ष 2008-09 से प्रारंभ

करके यथासंभव क्षति पैरामीटरों से संबंधित आंकड़ों का सत्यापन किया तथा जांच शुरुआत नोटिस वर्ष 2008-09 से 2011-12 (दिसम्बर 2011 तक) के आयात एवं क्षति आंकड़ों सहित जारी किया गया। तदुपरांत आवेदकों ने जनवरी से मार्च, 2012 तक आंकड़े प्रस्तुत किये गये। तीन माह की अतिरिक्त जानकारी सभी संबंधित को उपलब्ध कराई गई और रक्षोपाय नियमावली, 1997 के नियम 6(7) के अंतर्गत यथापेक्षित सार्वजनिक फाइल में रखी गयी।

14. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया कि वर्ष 2008-09 के आंकड़ों को नकार देने की प्ली की अनुमति नहीं देनी चाहिए क्योंकि यह विधिविरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, कार्बन ब्लैक, 1998 मामले के अनुरूप, जांच शुरुआत के उत्तरवर्ती आंकड़ों को रिकार्ड में नहीं लिया गया।

15. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि चयन की गई अवधि पर्याप्त रूप से लंबी होनी चाहिए जिससे कि संबंधित आयातों की मौजूदगी के संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सके और सीजनल विभिन्नताओं को निष्क्रिय करने के लिए वित्त वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक आंकड़ों पर विचार किया गया है। जांच शुरुआत नोटिस में दिसम्बर, 2011 तक के आयात आंकड़ों पर विचार किया गया। तब से, आयात आंकड़ों को मार्च, 2012 तक अद्यतन बना लिया गया। विचार किया गया। तब से, आयात आंकड़ों को मार्च, 2012 तक अद्यतन बना लिया गया। जहां तक वर्तमान जांच के लिए वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक की अवधि को लिया गया है। जहां तक इस तर्क का संबंध है कि मंदी के कारण वर्ष 2008-09 असामान्य अवधि है और इस विचार याचिका में उल्लिखित अवधि की उत्तरवर्ती अवधि के लिए विचार करना तार्किक रूप से सही है। याचिका/ जांच शुरुआत नोटिस में दिसम्बर, 2011 तक के आंकड़े शामिल हैं। हालांकि हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया की अप्रैल-दिसम्बर, 2011 के आंकड़ों को वार्षिकीकृत नहीं किया जा सकता है। इसलिए मार्च, 2012 तक के आंकड़ों पर विचार किया जाना उपर्युक्त एवं आवश्यक है।

#### घ. तारीख का स्रोत

16. वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक के आयात आंकड़ों को, जांच शुरुआत नोटिस में पहले से ही लिए गये आंकड़ों के अनुरूप डीजीसीआईएस से लिया गया है और वर्ष 2011-12 को आईबीआईएस से लिया गया है घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में प्रस्तुत वर्ष 2011-12 की तीसरी तिमाही के विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों संबंधित आंकड़ों का इस निदेशालय द्वारा यथासंभव सीमा तक सत्यापन किया गया है। इन सत्यापित आंकड़ों पर क्षति विश्लेषण के लिए विचार किया गया है। तथापि, वर्ष 2011-12 की तीसरी तिमाही तक के सभी

आंकड़ों को, विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों के बारे में, आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित लागत विवरण के अनुरूप आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित लागत विवरण के अनुरूप अद्यतन कर लिया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए आईबीआईएस आयात आंकड़ों पर निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है: -

(क) निदेशालय में उपलब्ध वर्ष 2011-12 के लिए डीजीसीआईएस आंकड़े संपूर्ण वित्त वर्ष के लिए नहीं हैं, जिसके अभाव में इनका वार्षिकीकरण करना पड़ा जो आयात आंकड़ों का वार्षिकीकरण करने के विरुद्ध सुनवाई के पश्चात अपने प्रस्तुतिकरण में कोरिया सरकार नामक एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा उठायी गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त नहीं होगा।

(ख) वर्ष 2011-12 के लिए आईबीआईएस आंकड़े संपूर्ण वर्ष के उपलब्ध हैं और यह लेनदेन बार भी है जिसकी एलसीपीएमए नामक एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा अपनी सुनवाई पश्चात प्रस्तुतिकरण में मांग की गई है।

(ग) यहां तक कि घरेलू उद्योग ने भी वर्ष 2011-12 के लिए डीजीसीआईएस आंकड़ों की यथार्थता के संबंध में इस आधार पर प्रश्न उठाया है कि यह देश में डायोक्टाइल थैलेटके लेनदेन बार संपूर्ण आंकड़ों को नहीं दर्शाता है। उन्होंने वर्ष 2011-12 के लिए लेनदेन बार आयात आंकड़े आईबीआईएस से प्रस्तुत किये हैं और उसके साथ उनपर विचार करने का अनुरोध करते हुए एक पत्र भी भेजा गया है।

### इ. प्रस्तुत जानकारी की गोपनीयता

17. घरेलू उद्योग ने गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराई है और अनुरोध किया है कि प्रस्तुत जानकारी/ आंकड़ों को गोपनीयता प्रदान कराई जाय। घरेलू उद्योग ने सभी प्रस्तुतीकरणों का अगोपनीय पाठ भी प्रदान कराया है जिसमें रक्षोपाय नियमावली, 1997 और व्यापार नोटिस सं. एसजी/टीएन/1/97 दिनांक 6.9.1997 भी शामिल है।

18. रक्षोपाय नियमावली के नियम 7 और रक्षोपाय संबंधी डब्लू टीओ करार के अनुच्छेद 3.2 में गोपनीयता का प्रावधान है। आवेदकों से ऐसी जानकारी का प्रकटन करने की अपेक्षा नहीं कि जाती है जो किसी व्यक्तिगत कंपनी के लिए गोपनीय सूचना है और जिसका प्रकटन करना कंपनी के व्यवसाय हित को गंभीर क्षति कर सकते हैं, जो सार्वजनिक रूप से प्रकट न कि गई हो और जिसे आवेदकों ने विगत में आम जनता के समक्ष उसका प्रकटन कर दिया हो तदनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा यथा अपेक्षित गोपनीयता की अनुमति दे दी गई।

### ख. संवर्धित आयात:

19. सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख में रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की

केन्द्र सरकार की शक्ति का उल्लेख किया गया है और उसमें निम्नलिखित प्रावधान है:

1. “यदि केन्द्र सरकार, उपयुक्त समझी जाने वाली ऐसी जांच करने के पश्चात्, संतुष्ट है कि किसी वस्तु का भारत में इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी स्थितियों में आयात किया जा रहा है जिससे कि यह घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचा रहा हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर रहा हो तो, यह, सरकारी राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा उस वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर सकती है”।
20. इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क टैरिफ़ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 2(ग) में निम्नलिखित प्रावधान है:

“(ग) ‘संवर्धित मात्रा’ में आयातों में वृद्धि शामिल है जो वह समग्र रूप से हो या घरेलू उत्पादन के संगत हो।”

21. नियम में यह निर्धारण करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या विचाराधीन उत्पाद का आयात अधिक मात्रा में किया जा रहा है, यह रक्षोपाय के लिए आवेदन करने हेतु एक आधारभूत पूर्वापेक्षा है। यह निर्धारित करने के लिए क्या विचाराधीन उत्पाद के आयात में “इतनी मात्रा में” “वृद्धि” हुई है कि रक्षोपाय करने के उद्देश्य के लिए उचित है, नियमों में दर और आयातों में वृद्धि की मात्रा का घरेलू उत्पादन और खपत के संबंध में तथा समग्र रूप से विश्लेषण करने की आवश्यकता है, जैसा कि पैनल ने धारित किया है और बाद में अजेन्टीना-फूटवियर<sup>1</sup> मामले में अपीलीय निकाय द्वारा इसकी पुष्टि भी गई।
22. अपने इस मूल्यांकन में कि क्या अजेन्टीना के प्राधिकारियों ने जांच में अनुच्छेद 2.1 तथा 4.2(क) के अंतर्गत आयातों में अपेक्षित वृद्धि प्रदर्शित की है, अजेन्टीना फुटवियर मामला<sup>2</sup> में पैनल ने निम्नलिखित उल्लेख किया:

... करार में आयातों में न केवल वृद्धि (अर्थात् कोई वृद्धि) बल्कि ऐसी ... मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए जो गंभीर क्षति कारित कर सके इस करार में किसी ऐसे संख्यात्मक मार्ग दर्शन का प्रावधान नहीं है कि इसका निर्णय कैसे किया जाएगा और हमारे विचार से न ही ऐसा किया जा सकता है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि यह अपेक्षा निरर्थक है। इसके विपरीत हमें विश्वास है कि इसका आशय है कि आयातों में वृद्धि का निर्णय इसके पूर्ण संदर्भ में, खासकर अनुच्छेद 4.2(क) द्वारा यथापेक्षित इसकी दर “दर और राशि” के संदर्भ में किया जाना चाहिए। अतः यह निर्णय करते समय कि आयातों में वृद्धि अनुच्छेद 2.1 के अनुसार 2.1 के अनुसार “ऐसी मात्रा में हुई है” कि संपूर्ण जांच अवधि में आयात के स्तर में हुए परिवर्तन पर विचार किया जाना, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अपरिहार्य प्रतीत होता है।

23. आयातों में वृद्धि की प्रकृति के संबंध में अजेन्टीना फुटवियर(ईसी)<sup>3</sup> मामले में अपीलीय निकाय ने, पैनल के विरुद्ध, यह धारित किया कि आयातों में यह वृद्धि अभी हाल ही में, अचानक, तीव्र और इतनी अधिक मात्रा में हुई हो कि उसे गंभीर क्षति हुई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हुई हो। संगत उद्धरण निम्नलिखित है:

“131. यह निर्धारण करना कि आयातों में “ऐसी मात्रा में वृद्धि” की अपेक्षा को पूरा किया जाता है, केवल गणितीय या तकनीकी निर्धारण नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में जांच के लिए सामान्य रूप से यह प्रदर्शित करना ही पर्याप्त नहीं है कि इस वर्ष के आयात पिछले वर्ष के आयातों- या पांच वर्ष पहले के आयातों से अधिक थे। साथ ही, आयातों की कोई भी संवर्धित मात्रा पर्याप्त नहीं होगी, हालांकि यह बात दोहराने जैसा लगता है। यह वृद्धि ‘ऐसी बढ़ी हुई मात्रा’ में होनी चाहिए की रक्षोपाय साधन के लिए आवेदन करने हेतु अपेक्षा को पूरा करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर सके या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर सके। और यह भाषा रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 2.1 और जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद XIX:1(क) में, हमारा विश्वास है कि, अपेक्षित है कि आयातों में यह वृद्धि अभी हाल ही में, अचानक, पर्याप्त, काफी तीव्र और परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूपों में इतनी भारी मात्रा में हुई हो कि इससे ‘गंभीर क्षति’ हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो”।

24. यू. एस — हीट ग्लुटेन<sup>4</sup>, में “ऐसी संवर्धित मात्रा” वाक्यांश को निम्नलिखित रूप से स्पष्टीकृत किया गया है:

“8.31 जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद XIX:1(क) और रक्षोपाय संबंधी करार(“एसए”) के अनुच्छेद 2.1 में आयातों में केवल “वृद्धि” का ही उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत, संबंधित उत्पाद के आयातों में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक प्रकृति की ‘वृद्धि’ की अपेक्षा की जाती है। जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद XIX:1(क) और रक्षोपाय संबंधी करार(“एसए”) के अनुच्छेद 2.1 में अपेक्षा की जाती है कि किसी उत्पाद का संबंधित सदस्य के भू-भाग में इतनी अधिक मात्रा (घरेलू उत्पादन के समग्र या संगत रूप) में की जा रही है कि इससे गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की

<sup>1</sup> अजेन्टीना- फुटवियरसंबंधी अपीलीय निकाय रिपोर्ट (ईसी) डब्लू.टी/डीएस 121/एबी/आर दिनांक 14 दिसम्बर, 1999

<sup>2</sup> अजेन्टीना-फुटवियर (ईसी) संबंधी पैनल रिपोर्ट डब्ल्यू.टी/डी एस 121/आर दिनांक 25 जून, 1999

चुनौती हुई हो। अतः, आयातों में केवल हल्की सी वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी। बल्कि, हम अजेन्टीना—फुटवियररक्षोपाय में अपीलीय निकाय के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि यह वृद्धि पर्याप्ततः हाल के समय में, तीव्र और परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूपों में इतनी अधिक हुई हो कि इससे गंभीर क्षति हो रही हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो रही हो।

25. यू.एस.—लाइन पाइप में पैनल ने यह निष्कर्ष निकाला, जिसकी अपीलीय निकाय द्वारा समीक्षा नहीं की गई, कि शब्द 'हाल ही में' का आशय "पूर्वापेक्षी विश्लेषण" है; परन्तु न तो इसमें प्राधिकारी के निर्णय से तुरंत पहले की स्थिति का विश्लेषण करने का आशय है और न ही इसका आशय यह है कि इस विश्लेषण में जांच की अवधि के तुरंत पश्चात की स्थितियों पर अनन्यतः प्रकाश डाला जाना चाहिए। संगत उद्दरण निम्नलिखित है:

"7.024 हम नोट करते हैं कि अजेन्टीना-फुटवियररक्षोपाय में अपीलीय निकाय ने यह पाया कि वाक्यांश "आयात किया जा रहा है" का आशय यह है कि आयातों में यह वृद्धि अचानक और अभी हाल ही की अवधि में हुई हो। कोरिया के अनुसार वाक्यांश "..... ऐसी बढ़ी हुई मात्रा में आयात किया जा रहा है" का उल्लेख 'प्राधिकारी के निष्कर्ष से ठीक पहले की अवधि' से है। शब्द 'अभी हाल ही में' जिसका अपीलीय निकाय ने 'आयात किया जा रहा है' वाक्यांश का विश्लेषण करते हुए किया है, को 'काफी विगत समय; जो घटित हुआ है, प्रतीत हुआ है,

मौजूदा होना प्रारंभ हुआ है या अभी हाल ही में मौजूद हुआ है' के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में शब्द 'अभी हाल ही में' का आशय एक तरह के पूर्वापेक्षी विश्लेषण से है। इसका आशय प्राधिकारी के निर्णय से तत्पात पहले उपस्थित स्थितियों का विश्लेषण करने से नहीं है। न ही इसका आशय यह है कि विश्लेषण में अनिवार्यतः जांच अवधि के अंत में मौजूद हालातों के विश्लेषण पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। हम मानते हैं कि कोई विश्लेषण जिसमें 1998 के पहले सेमेस्टर की तुलना वर्ष 1999 के पहले सेमेस्टर से की गई है, इस अपेक्षा कि आयातों में यह वृद्धि 'अभी हाल ही में' हुई, से असंगत है।"

<sup>1</sup> अजेन्टीना - फुटवियर(ईसी) संबंधी अपीलीय निकाय की रिपोर्ट डब्लू.टी./डीएस 121/एवी/आर दिनांक 14 दिसम्बर, 1999  
<sup>2</sup> यूएस - फ्लीट ग्लुटेन. संबंधी पैनल रिपोर्ट डब्लू.टी./डीएस 166/ आर दिनांक 31 जुलाई, 2000

26. डायोक्टायल थैलेटबढ़े हुए आयातों का विश्लेषण उपर्युक्त मूल्यांकन के आलोक में किया गया है। भारत में डायोक्टायल थैलेटका आयात कई देशों से और प्राथमिकतः कोरिया

गणराज्य, मलेशिया और ताइवान से किया जाता है। चमड़े के वस्त्र एवं प्लास्टिक विनिर्माण एसोसिएशन (एलसीपीएमए) द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस उत्पाद के घरेलू उत्पादक संवर्धन का भारी मात्रा में आयात करते रहे हैं। अतः आयातों का विश्लेषण घरेलू उद्योग द्वारा किये गये इन आयातों को छोड़कर किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने यह भी कहा है कि अब अधिकांश आयात या तो आयातकों द्वारा या उपभोक्ताओं द्वारा किया जा रहा है और बढ़े हुए आयातों तथा उससे हुई क्षति का विश्लेषण करते समय घरेलू उद्योग द्वारा किये गए आयातों का अपवर्जन करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। यह नोट किया गया कि घरेलू उद्योग के संघटकों द्वारा किये गये आयात का अपवर्जन करने के बाद के आयातों का विश्लेषण करना निम्नलिखित कारणों से उचित होगा:

- क. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मांग की गई है कि आयातों में वृद्धि और उससे हुई क्षति घरेलू उद्योग द्वारा किये गये आयातों के कारण हुई है और इसलिए घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव के रूप में संवर्धित आयातों का विश्लेषण करने के उद्देश्य से यह उपयुक्त होगा कि आयातों की प्रवृत्ति और प्रश्नाधीन उत्पाद के कुल आयातों में से घरेलू उद्योग द्वारा किये गये आयातों का अपवर्जन करके घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों में परिणामी परिवर्तन का विश्लेषण किया गया जाए।
- ख. आवेदनकर्ताओं ने यह तर्क भी दिया है कि उनके द्वारा किये गए आयातों को आयातों और घरेलू उद्योग पर उनके प्रभाव का आकलन करने के उद्देश्य के लिए सकल आयातों से हटा दिया जाना चाहिए।
- ग. घरेलू उद्योग पर बढ़े हुए आयातों के प्रभाव का निर्धारण करना अपेक्षित है। अतः, घरेलू उद्योग द्वारा स्वयं किये गये आयातों का, किसी भी हाल में, उनपर विपरीत प्रभाव नहीं होगा।
- घ. नियमों में यह अपेक्षा की जाती है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी न केवल बढ़े हुए आयातों की जांच करें बल्कि उन स्थितियों की जांच भी करें जिनमें यह आयात किये गये हैं। धारा 8ख(1) महानिदेशक से यह अपेक्षा करती है कि वह जांच करें कि क्या वस्तु का आवात भारत में इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी हालातों में किया जा रहा है कि जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो। अतः वह स्थितियां जिनके अंतर्गत बढ़े हुए आयातों की सूचना दी गई हैं, भी संगत हैं।
- ঙ. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण, हर हाल में, गैर विभेदकारी आधार पर किया जायेगा और इसलिए घरेलू उद्योग या किसी अन्य द्वारा किये गए आयात रक्षोपाय शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

[भाग II—खण्ड 3(i)]

27. उपर्युक्त के आलोक में, मैंने संवर्धित आयातों का निर्धारण डायोक्टायल थैलेट के कुल आयातों में से घरेलू उद्योग द्वारा स्वयं किये गये आयातों को घटाकर किया है।

28. यह निर्धारित किया जाता है कि भारत में डायोक्टायल थैलेट का आयात (घरेलू उत्पादकों द्वारा किये गये आयात का अपवर्जन करने के पश्चात) इतनी अधिक मात्रा में और समग्र रूप से तथा घरेलू उत्पादन एवं खपत की तुलना में समस्या स्थितियों में किया गया है जिससे कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न हो गया है। जो निम्नलिखित है:

(क) आयात:

विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कुल आयात	मी.टन	40,608	35,210	35,346	41,632
घरेलू उद्योग द्वारा किये गए आयात	मी.टन	13,312	13,726	12,798	2,665
आयात (घरेलू उद्योग द्वारा किये गये आयातों को छोड़कर)	मी.टन	27,296	21,484	22,548	38,967

29. आयातों में समग्र एवं संगत दोनों रूपों में भारी वृद्धि हुई है। आयात जो वर्ष 2008-09 27,296 मी.टन थे घटकर वर्ष 2009-10 में 21,484 मी.टन रह गये और तत्पश्चात (2010-11 में) बढ़कर 22,548 मी.टन तथा वर्ष 2011-12 में 38,967 मी.टन हो गए। यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2008-09 में आयात इस अवधि में मंदी के आंशिक प्रभाव के कारण बढ़े थे और तत्पश्चात वर्ष 2009-10 में इनमें गिरावट आ गयी। तथापि, उसके बाद भी आयातों में वृद्धि हुई जो (2009-10 में) 21484 मी.टन से बढ़कर (2011-12) में 38,967 मी.टन हो गये। अर्थात् वृद्धि 81% हुई।

(ख) उत्पादन के संबंध में आयात:

यह देखा जा सकता है कि जांचाधीन अवधि के दौरान कुल घरेलू उत्पादन की तुलना में आयातों में भी वृद्धि हुई है, जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है:

विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कुल भारतीय आयात	मी.टन	63,757	74,221	84,710	76,821
आयात (घरेलू उद्योग द्वारा आयात को छोड़कर)	मी.टन	27,296	21,484	22,548	38,967
उत्पादन के संबंध में आयात	%	43%	29%	27%	51%

कुल उत्पादन की तुलना में आयात वर्ष 2010-11 में 27% थे जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 51% हो गए, यह वृद्धि लगभग दोगुनी है।

**(ग) खपत/ मांग के संबंध में आयात**

विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
मांग/ खपत	मी.टन	89,708	94,202	101,704	106,093
आयात (घरेलू उद्योग द्वारा आयात को छोड़कर)	मी.टन	27,296	21,484	22,548	38,967
खपत/ मांग के संबंध में आयात	%	30%	23%	22%	37%

30. इसी तरह, आयातों ने घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर कुल मांग में भी अपना हिस्सा बढ़ा लिया, जिससे क्षति हुई। वर्ष 2009-10 और 2011-12 के बीच खपत में वृद्धि 13% हुई जबकि आयातों में वृद्धि 81% हुई।

31. इस प्रकार यह देखा जाता है कि भारत में डायोकटायल थैलेट का आयात (घरेलू उत्पादकों द्वारा किये गये आयात को छोड़कर) समग्र रूप में तथा घरेलू उत्पादन एवं खपत की तुलना में इतनी अधिक मात्रा में किये गये कि उससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गयी। यह धारित किया जाता है कि आयातों में वृद्धि में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति हैं जो अधिनियम की धारा 8ख के आशय के अंतर्गत “संवर्धित आयात” बनने के लिए पर्याप्त है।

32. जहां तक इस तर्क का सम्बंध है कि कोरिया के निर्यातों में 3382 मी.टन से कम होकर वर्ष 2011 की उसी अवधि में 11924 मी.टन रह गये, यह नोट किया जाता है कि रक्षोपाय जांच के अंतर्गत किसी एक देश द्वारा किये गये आयात का तर्क पूर्णतः असंगत है क्योंकि आयातों में वृद्धि के लिए विभिन्न स्रोतों से संचयी आयातों पर विचार किया गया है।

**अप्रत्याशित विकाश :**

33. यह नोट किया जाता है कि अप्रत्याशित विकास का विश्लेषण करने के लिए अपनी जाने वाली किसी विधि के संबंध में भारतीय नियमों या रक्षोपाय संबंधी डब्लू.टीओ करार में कोई विशिष्ट अपेक्षा नहीं है। रक्षोपाय संबंधी करार में उस तरीके के संबंध में कोई विशिष्ट वर्णन नहीं किया गया है जिसे अपनाया जाना चाहिए या कोई ऐसा पैरामीटर नहीं बताया गया है कि जिसे अप्रत्याशित विकास का निर्धारण करने के लिए पूरा किया जाना अपेक्षित है। तथापि, उन परिस्थितियों की जांच करना महत्वपूर्ण है जिनके कारण आयातों में वृद्धि हुई।

34. अजेन्टीना — फुटवियर(ईसी) और कोरिया — डेयरी मामले में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि "डब्लू टी ओ करार के प्रभावी होने के पश्चात अधिरोपित किसी भी रक्षोपाय साधन को रक्षोपाय संबंधी करार और गाट 1994 के अनुच्छेद XIX दोनों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना जरुरी है। गाट 1994 के अनुच्छेद XIX में निम्नलिखित उल्लेख है:

1. (क) यदि, अप्रत्याशित विकास के परिणामस्वरूप और इस करार, टैरिफ रियायतों के अंतर्गत, किसी संविदाकारी पक्षकार द्वारा अपने ऊपर लिए गए इसी भूदायित्व के प्रभावस्वरूप यदि किसी उत्पाद का आयात संविदाकारी पक्षकार के भूभाग में इतनी अधिक मात्रा में और ऐसे हालातों में किया जाता है कि उस भूभाग में उसके समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पादों के घरे तू उत्पादकों को गंभीर क्षति होती है अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न होती है तो संविदाकारी पक्षकार इन उत्पादों के संबंध में उस सीमा तक और ऐसे समय तक आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा जो ऐसी क्षति को रोकने या उसका उपचार करने के लिए आवश्यक हो तथा वह अपने संपूर्ण या आंशिक दायित्व को समाप्त करने या रियायतों को वापस लेने या उसमें संशोधन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

35. अजेन्टीना- फुटवियर (ई सी मामला) में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि अप्रत्याशित विकास वाक्यांश का आशय ऐसे विकास से है जो अप्रत्याशित रूप से हुआ हो। अप्रत्याशित विकास वाक्यांश का आशय ऐसे विकास से है जो अप्रत्याशित रूप से हुआ हो। "अप्रत्याशित विकास" अपेक्षा करता है कि वह विकास जिसके कारण उत्पाद का आयात इतनी बढ़ी हुई मात्रा में और ऐसे हालात में किया जा रहा है जिससे कि घरेलू उत्पादकों होना चाहिए। निकाय ने उसी मामले में ह एक गाट पैनल रिपोर्ट को लोट किया जिसमें होना चाहिए। निकाय ने उसी मामले में ह एक गाट पैनल रिपोर्ट को लोट किया जिसमें होना चाहिए। कोरिया- डेयरी मामले में अपीलीय निकाय ने निर्णय दिया कि अप्रत्याशित विकास वे विकास हैं जो सदस्य द्वारा दी गई वचनबद्धता के समय प्रत्याशित न हों।

36. अर्जेन्टीना में अपीलीय निकाय — फुट वियर (ईसी) ने तब यह माना कि "अप्रत्याशित विकास" की जरूरत, सुरक्षापार्यों को अधिरोपित करने के लिए पृथक "शर्त" स्थापित नहीं करकती है लेकिन "परिस्थितियों" की कतिपय शर्तों का वर्णन करती है।

37. यू.एस स्टील सुरक्षापार्यों<sup>5</sup> के पैनल का मानना है कि कई घटनाओं के मिल जाने से अप्रत्याशित विकास का आधार बन जाता है:

"..... यूनाइटेड स्टेट इस बात पर बल देता है कि यूएस डालर का मजबूत हो

जाना एक विकास था जो एरिया और पूर्य यू एस एस आर में मुद्रा के अभाव और दूसरे बाजारों द्वारा स्टील से इंकार कर दिए जाने के कारण “यूनाइटेड स्टेट्स” में स्टील की बढ़ती मांग जैसी दूसरी गतिविधियों के साथ मिलकर आयात बढ़ाने का कारण बना।”

38. मैंने पाया कि आवेदकों ने आयात में वृद्धि के लिए कई कारण बताये हैं जिनका संक्षेप में वर्णन निम्नलिखित है:

(क) थैलिक एनहाइड्राइड का विनिर्माण करने के लिए नये संयंत्रों की स्थापना और तदद्वारा थैलिक एनहाइड्राइड की अपनी क्षमता में विस्तार करना। थैलिक एनहाइड्राइड के उत्पादन में बढ़ोत्तरी से चीन में भी थैलिक एनहाइड्राइड के उत्पादन में वृद्धि हुई इससे तृतीय देशों के उत्पादकों को डायोक्टायल थैलेट का चीन को निर्यात करने के बाजार अवसरों में कमी आयी। इसके परिणाम स्वरूप यह उत्पादक डीओपी का निर्यात करने के लिए नये बाजारों की तलाश कर रहे हैं। प्रमुख निर्यातक देशों से चीन को डायोक्टायल थैलेट के निर्यात में कमी निम्नलिखित तालिका से देखी जा सकती है:

अवधि	विश्व	चीन
2007	2,38,411	1,40,534
2008	2,11,208	1,08,002
2009	2,07,669	86,883
2010	1,85,132	68,172
2011	1,93,678	32,404

स्रोत: कोरिया सीमा शुल्क

<sup>5</sup> डब्ल्यू टी ओ की अपीलीय निकाय रिपोर्ट 36 कोरिया डेयरी मामला का पैरा 86

डायोक्टायल थैलेट का मत्तेशिया से निर्यात

अवधि	विश्व	चीन
2007	75,954	18,262
2008	62,768	9,969
2009	68,026	16,689
2010	62,344	13,959

[ भाग II—खण्ड 3(i) ]

2011	37,409	3,224
------	--------	-------

स्रोत: मलेशिया सीमा शुल्क

## डायोक्ट्रायल थैलेट का ताइवान से निर्यात

अवधि	विश्व	चीन
2007	1,60,843	1,32,649
2008	1,08,075	81,115
2009	1,73,896	1,55,783
2010	84,597	70,212
2011	46,343	19,502

स्रोत: ताइवान सीमा शुल्क

ग) इन देशों से भारत को किया गया निर्यात निम्नलिखित है:-

अवधि	कोरिया गणराज्य	ताइवान	मलेशिया	कुल
2008-09	13,424	4,875	11,971	30,270
2009-10	13,967	1,340	15,657	30,964
2010-11	19,223	1,605	6,174	27,002
2011-12	16,798	17,386	6,698	40,882

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कोरिया गणराज्य, मलेशिया और ताइवान से भारत को आयात उच्च स्तर पर बने रहे और जांच अवधि के दौरान संचयी रूप से इनमें 30,270 मी.टन वृद्धि होकर 40,882 मी.टन हो गई और वर्ष 2010-11 में हुए 27002 मी.टन की तुलना में वर्ष 2011-12 में बढ़कर 40882 मी.टन हो गए जो कुल आयातों की (घरेलू उद्योग के आयात सहित) लगभग 98% वृद्धि है।

ग) इसके अतिरिक्त डीओपी के निर्यात में यह वृद्धि प्राप्टी की कीमतों में वृद्धि के कारण अभी हाल ही में अधिक प्रभावी हुई और पीवीसी बाजार में घटने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई। चीन में आवास, निर्माण और रियल एस्टेट में विपरीत प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई जिसके कारण चीन की सरकार को कड़े नियामक उपाय करने पड़े।

आईसीआईएस कीमत निर्धारण (थैलिक एनहाइड्राइड), 18 नवम्बर, 2011  
उत्पादकों ने कहा कि चीन के क्रेता चीन में संपदा विकास के भय और देश में बढ़ती मुद्रा स्फीति के कारण अभी भी भावनात्मक रूप से सचेत हैं

आईसीआईएस कीमत निर्धारण (थैलिक एनहाइड्राइड), 28 अक्टूबर, 2011

चीन में पोलीविनायल क्लोराइड (पीवीसी) के कई उत्पादकों ने, चीन की प्रोपर्टी बाजार में आने वाले बड़े सुधार के भय से डीओपी सामग्री का भंडारण करना बंद कर दिया है। पीवीसी खिड़की पैनलों, दरवाजें के फ्रेमों, चमड़े के सोफा और पाइपों का निर्माण करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला एक पोलीमर है।

आईसीआईएस कीमत निर्धारण (थैलिक एनहाइड्राइड), 23 दिसम्बर, 2011

क्षेत्रीय उत्पादकों और व्यापारियों ने कहा कि क्रेता भारी खरीद करने में अभी भी सचेत होंगे, क्योंकि वे अपने घरेलू स्थिल एस्टेट बाजार की प्रगति के लिए चिंतित थे।

चीन में स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पूरे राष्ट्र में शहरों में सरकार द्वारा प्रायोजित भूमि की नीलामी में अभी हाल ही के महीनों में मंदी आई, जिससे उपभोक्ता कम हो गए।

आई सी आई एस कीमत निर्धारण (थैलिक एनहाइड्राइड) 30 दिसम्बर, 2011

तथापि, क्रेता चीन की प्रापर्टी बाजार की प्रगति के प्रति चिन्तित हैं। देश का कमी चोटी का बाजार रहा प्रापर्टी मार्केट में अब कमी आ गयी क्योंकि चीन की सरकार ने अप्रैल से नीतियों को सख्त बनाना शुरू कर दिया।

इस माह देश के केन्द्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन में किए गए निर्णय के अनुसार चीन अपनी प्रापर्टी मार्केट संबंधी विनियमन नीतियां कायम रखेगा जिससे वह आवास कीमतें उपयुक्त स्तर पर ला सके।

घ) यतः, चीन, जो डीओसी और थैलिक एनहाइड्राइड का निवल आयातक था, ने ओलिम्पिक खेलों के पश्चात अपनी अत्यधिक क्षमता और घरेलू बाजार में शून्य मांग के कारण यूरोजोन तथा अन्य देशों को निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। परन्तु यूरोजोन में क्रृषि संकट के आलोक में इन बाजारों में भी डी ओ पी की मांग बढ़ने लगी जिससे डीओपी तथा थैलिक एनहाइड्राइड के उत्पादकों को अपना माल उपलब्ध कीमतों पर डम्प करना पड़ा।

आई सी आई एस कीमत निर्धारण (थैलिक एनहाइड्राइड) 16 दिसम्बर, 2011

इसका आशय यह है कि पी ए उत्पादकों को मार्ग 2012 में कठिन हो जाएगा क्योंकि पी ए डायोक्यल थैलेट के उत्पादन में किया जाने वाला एक डीडस्टाक है। डीओपी का प्रयोग निर्माण सामग्री एवं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने में किया जाता है। यूरोजोन इन उत्पादों का चीन एवं दक्षिणपूर्व दोनों में भारी आयातक है।

### ભાગ II—ખણ્ડ 3(i)]

तथापि, क्षेत्रीय व्यापारियों ने सचेत किया है कि वैश्विक अर्थिक अनिश्चितता और योजना के वित्तीय संकट के कारण कीमत में यह वृद्धि क्षणभंगुर हो सकती है।

यूराजान के वित्ताय सपाट दो दिन 23 दिसम्बर, 2011  
आई सी आई एस कीमत निर्धारण (थैलिक एनहाइड्राइड) 23 दिसम्बर, 2011

आई सी आई एस कोमत निधारण (यालक रनात्तम्भु) ॥  
क्रेताओं और व्यापरियों ने कहा कि वे यूरो जोन के सतत ऋण संकट के प्रति  
चिन्तित हैं। यूरोजोन निर्माण सामग्री और उपभोक्ता वस्तुओं का चीन से भारी मात्रा  
में आयात करता है।

आई सी आई एस कीमत निर्धारण (थैलिक एनहाइड्राइड) 20 दिसम्बर, 2011

आई सी आई एस कामत निधारण (यात्रा) रणनीति इसी बीच यूरो जॉन में क्रृष्ण संकट बरकरार रहा और निर्माण उद्योग की क्रय रुचि कम हो गयी क्योंकि अति संयमता की धारणा क्षेत्र में सर्वत्र बढ़ी रही।

कम हा गया क्याक जात रापड़ा।

39. रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए प्रस्तुतिकरणों को ध्यान में रखते हुए यह पाया गया कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में कई कारणों से वृद्धि हुई। चीन में थैलिक एनहाइड्राइड के नए संयंत्र की स्थापना से थैलिक एनहाइड्राइड के उत्पादन में वृद्धि हुई और डायोकटायल थैलेट का उत्पादन भी बढ़ा जिससे तृतीय देशों के विदेशी उत्पादों द्वारा डायोकटायल थैलेट का चीन को निर्यात करने के अवसरों में कमी आई। कोरिया और ताईवान के निर्यातकों को अपने उत्पाद के लिए विकासशील बाजारों की तलाश करने को मजबूर होना पड़ा और भारत, उनकी सर्वाधिक अर्थक्षम पसंद होने के कारण भारत में इसके आयातों में वृद्धि हुई। इन सभी तथ्यों को डीओपी के आयात में वृद्धि को अप्रत्याशित कारणों के रूप में माना गया। यह दर्शाता है कि कोरिया और ताईवान से अप्रत्याशित कारणों के रूप में माना गया। यह दर्शाता है कि जिससे आयात बढ़े और डायोकटायल थैलेट के आयात में वृद्धि एक अप्रत्याशित घटना है जिससे आयात बढ़े और उनसे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई या घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की स्थिति उत्पन्न हो गयी।

ज. गंभीर क्षति और गंभीर क्षति की चुनौतीः

ज. गंभीर क्षति और गम्भार क्षात का युक्ताता।

40. "गंभीर क्षति" का आशय ऐसी क्षति से है जिससे घरेलू उद्योग के निष्पादन में समग्र कमी आए; और "गंभीर क्षति" की चुनौती का आशय गंभीर क्षति को स्पष्ट एवं आसन्न संकट से है।

आसन्न संकट से है। 41. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.2(क) और सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और उसका आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 8 में यह अपेक्षा की जाती है कि गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का मूल्यांकन करने के लिए कुछ सूचीबद्ध तथ्यों तथा अन्क्षति या अन्क्षति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तथापि, इन उपबंधों में यह स्पष्ट नहीं किया संगत तथ्यों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऐसा कोई भी मूल्यांकन मामलों के गया है कि इस मूल्यांकन से क्या प्रदर्शित होना चाहिए। ऐसा कोई भी मूल्यांकन मामलों के विशिष्ट तथ्यों और संवंधित उद्योग की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न उद्योगों के विभिन्न मामलों में अलग-अलग होगा। प्रत्येक सूचीबद्ध मामले का मूल्यांकन करने से

जरुरी नहीं है कि यह प्रदर्शित हो कि प्रत्येक तथ्य में “गिरावट आ रही है। उदाहरणार्थ, एक मामले में उद्योग में “समग्र हानिकरण” हो सकता है। अतः, सभी सूचीबद्ध तथ्यों तथा किसी अन्य संगत तथ्यों का तकनीकी परीक्षण करने के अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का उन सभी संगत तथ्यों का आधार पर मूल्यांकन किया जाए; जिनका उद्योग की स्थिति प्रभाव पड़ता है।

42. अजेन्टीना — फूटवीयर (ईसी) 6, में अपीलीय निकाय ने अनुच्छेद 4.1(क) में “गंभीर क्षति” की परिभाषा तथा अनुच्छेद 4.2(क) द्वे “सभी संगत तथ्यों” के मूल्यांकन के बीच संबंधों पर चर्चा की है:

“यदि घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति के संबंध में उन सभी संगत तथ्यों, जिनका उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, मूल्यांकन किया जाता है तभी यह निर्धारित किया जा सकता है कि क्या उद्योग की स्थिति में ‘महत्वपूर्ण समग्र हानिकरण’ हुआ है। यद्यपि अनुच्छेद 4.2(क) में तकनीकी रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि कुड़ सूचीबद्ध तथ्यों का ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और यह कि अन्य सभी संगत तथ्यों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए परन्तु उक्त प्रावधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उस मूल्यांकन से क्या प्रदर्शित होता है। स्पष्टतः ऐसा कोई भी मूल्यांकन अलग-अलग उद्योगों के लिए अलग-अलग मामलों में, किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों और संबंधित उद्योग की स्थिति के आधार पर, अलग-अलग होगा। प्रत्येक सूचीबद्ध तथ्य का मूल्यांकन जरुरी नहीं है कि यह स्पष्ट करें कि ऐसे प्रत्येक तथ्य में “गिरावट आ रही है। उदाहरणार्थ, एक मामले में हो सकता है कि बिक्री, रोजगार और उत्पादकता में भारी गिरावट हो जो उद्योग की स्थिति में “महत्वपूर्ण समग्र हानिकारण” दर्शाता हो और इस कारण वह गंभीर क्षति के निष्कर्ष को न्यायोचित ठहराएगा। वहीं किसी दूसरे मामले में, कोई निश्चिय तथ्य में गिरावट न आ रही हो, परन्तु ऐसा होते हुए भी समग्र स्थिति उस उद्योग की “भारी समग्र हानिकरण” प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार इस तकनीकी जांच के अतिरिक्त कि क्या सक्षम प्राधिकारियों ने किसी विशिष्ट मामले में सभी सूचीबद्ध तथ्यों की और किन्हीं अन्य संगत तथ्यों की जांच कर ली है हमारा विश्वास है कि पैनल को “गंभीर क्षति” का निर्धारण करने संबंधी अपनी समीक्षा करते समय रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.1 (क) में “गंभीर क्षति” की परिभाषा को ध्यान में रखना अनिवार्य है।”

43. यूएस- हीट ग्लूटेन, संबंधी पैनल द्वे, अपीलीय निकाय द्वारा परिपुष्ट एक निष्कर्ष में गंभीर क्षति के अर्थ के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया है कि,

“(क) यह निर्धारित कि क्या “महत्वपूर्ण समग्र हानिकारक” मौजूद है घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का, उन सभी संगत तथ्यों के आधार पर मूल्यांकन कम करना

आवश्यक है जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो।

.....  
(ह) म यह नहीं मानते हैं कि किसी उद्योग की समग्र महत्वपूर्ण हानिकारक स्थिति के लिए जांच किए गए प्रत्येक एकल तथ्य में नकारात्मक प्रवृत्ति होना आवश्यक है। बल्कि, प्रवृत्तियों की समग्र स्थिति और उनकी अन्योन्यक्रिया को गंभीर क्षति निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। अतः कई तथ्यों में ऐसे मोड निश्चिततः करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। जांचकर्ता प्राधिकारियों को चाहिए कि वे उनके गंभीर क्षति का निर्धारण नहीं करेंगे। जांचकर्ता प्राधिकारियों को चाहिए कि वे उनके समक्ष उपस्थित साक्ष्यों का आकलन करें और उनकी गंभीरता को देखे तथा इस तथ्य समक्ष उपस्थित साक्ष्यों का आकलन करें और उनकी गंभीरता को देखे तथा इस तथ्य का कारणात्मक एवं कारणों से युक्त स्पष्टीकरण दे कि यह तथ्य निर्धारण को समर्पित कैसे करते हैं।"

44. तदनुसार, गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का विश्लेषण करते समय नियमावली में उल्लिखित सभी तथ्यों तथा गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करने के संगत सभी अन्य तथ्यों पर विचार किया गया है। किसी एक तथ्य को निर्णायक के लिए संगत सभी अन्य तथ्यों पर विचार किया गया है। किसी एक तथ्य को निर्णायक के रूप में नहीं माना गया। संगत व्यवसाय चक्र के संदर्भ के अंतर्गत सभी संगत तथ्यों तथा प्रतिस्पर्धा की शर्तों, जो प्रभावित उद्योग से संगत हैं, पर विचार किया गया है। गंभीर क्षति प्रतिस्पर्धा की चुनौती का निर्धारण घरेलू उद्योग की उस समग्र स्थिति के मूल्यांकन पर या गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण घरेलू उद्योग की उस समग्र स्थिति पर प्रभाव है। आधारित है, जिनका उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव है।

.....  
‘अर्जेन्टीना- फुटवीयर संबंधी अपीलीय निकाय रिपोर्ट डब्ल्यू टी/डीएस 121 /एबी/आर दिनांक 14 दिसम्बर, 1999

7 यूएस-हीट ग्ल्यूटेन संबंधी पैनल रिपोर्ट डब्ल्यू टी/डीएस 166/आर 31 जुलाई, 2000

45. यह धारित किया जाता है कि डायोक्टायल थैलेट के बढ़े हुए आयातों से डायोक्टायल थैलेट के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति कारित की है और गंभीर क्षति की चुनौती कारित कर रहे हैं जैसा कि निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है।

#### क. मांग/खपत

46. भारत में इस उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत का निर्धारण घरेलू उद्योग की विक्री और सभी स्रोतों से आयात (घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों को छोड़कर) को शामिल करके किया गया है। यह नोट किया जाता है कि डायोक्टायल थैलेट की मांग में इस सम्पूर्ण अवधि में सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है।

वर्ष

यूनिट	2008-	2009-	2010-11	2011-12
-------	-------	-------	---------	---------

घरेलू उद्योग की विक्री	मी.टन	58,880	67,959	72,035	65,221
अन्य उत्पादकों की विक्री	मी.टन	3,532	4,759	7,121	1,905
आयात की मात्रा	मी.टन	27,296	21,484	22,548	38,967
कुल मांग/ खपत	मी.टन	89,708	94,202	101,704	106,093

47. यह देखा जाता है कि मांग में बढ़ोत्तरी से घरेलू उद्योग की विक्री में आधार वर्ष से 2011-12 तक केवल 11% की वृद्धि हुई परन्तु आधार वर्ष से 2011-12 तक आयातों में 43% की वृद्धि हुई।

#### ख. बाजार हिस्सा:

48. निम्नलिखित तालिका से यह स्पष्ट है कि कुल खपत में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी आई है।

बाजार हिस्सा (मांग में)	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
घरेलू उद्योग	मी.टन	66%	72%	71%	61%
उत्पादक (घरेलू उद्योग के अलावा)	मी.टन				
		4%	5%	7%	2%
आयात	मी.टन	30%	23%	22%	37%

घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जो (वर्ष 2008-09 में) 66% था, बढ़कर (2009-10 में) 72% हो गया और तत्पश्चात (वर्ष 2011-12 में) 61% हो गया। यह नोट किया जाता है कि आयातों का बाजार हिस्सा बहुत अधिक था और इस अवधि में मंदी के प्रभाव के कारण घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा वर्ष 2008-09 में बहुत न्यून था। वर्ष 2009-10 में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई। तथापि, इसमें उसके बाद भारी गिरावट आई।

#### ग. उत्पादन:

49. उत्पादन का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा अपने उत्पाद रिकार्ड में यथारिपोर्टित उत्पादन के आधार पर किया गया है। घरेलू उद्योग के उत्पादन से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित हैं।

विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कुल क्षमता	मी.टन	155,750	155,750	155,750	190,750
उत्पादन	मी.टन	60,242	69,468	77,492	74,943

50. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का उत्पादन (वर्ष 2008-09) में 60242 मी.टन से

[भाग II—खण्ड 3(i)]

बढ़कर (वर्ष 2009-10 में) 69468 मी.टन तथा (वर्ष 2010-11में) 77492 मी.टन हो गया। तथापि, उसके बाद उत्पादन में गिरावट आई और वर्ष 2011-12 में 74943 मी.टन हो गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि घरेलू उद्योग वर्ष 2011-12 में अपनी क्षमता में और वृद्धि कर ली थी, फिर भी इसके उत्पादन में कमी आई, यह स्पष्ट करता है कि विपरीत स्थितियां मौजूद थीं।

#### घ. घरेलू बिक्री:

51. घरेलू उद्योग की बिक्री का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा अपने फैक्टरी परिसर से घरेलू बाजार में भेजे गए माल अपने उत्पाद कर रिकार्ड में प्रदर्शित किए गए अनुसार, के आधार पर की जाती है। अधोलिखित तालिका में घरेलू उद्योग की कुल बिक्री और कुल निर्यात को दर्शाया गया है।

विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
बिक्री मात्रा- घरेलू	मी.टन	58,880	67,959	72,035	65,221
बिक्री मात्रा- निर्यात	मी.टन	1,326	1,892	4,274	10,023
बिक्री मात्रा-कुल	मी.टन	60,206	69,851	76,309	75,244

52. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री जो (वर्ष 2008-09 में) 58,880 मी.टन थी से बढ़कर (2009-10 में) 67,959 मी.टन तथा (2010-11) में 72,035 मी.टन हो गयी। तत्पश्चात घरेलू बिक्री घटकर वर्ष 2011-12 में 65,221 मी.टन हो गई। अभी हाल ही की अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है। आयात में वृद्धि से भी वर्ष 2011-12 की हालात में सुधार नहीं आया जब घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ और माल एकत्र होता रहा।

#### ड. क्षमता उपयोग :

53. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग निम्नलिखित है -

विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
संयंत्र क्षमता	मी.टन	155,750	155,750	155,750	190,750
विचाराधीन उत्पाद का उत्पाद	मी.टन	60,242	69,468	77,492	74,943
क्षमता उपयोग	%	39%	45%	50%	39%

54. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग (वर्ष 2008-09) में 39% था जो (2009-10 में) बढ़कर 45% तथा (2010-11में) बढ़कर 50% हो गया। तथापि क्षमता उपयोग में उसके बाद गिरावट आयी और वर्ष 2011-12 में घटकर 39% हो गया।

55. वर्ष 2011-12,में घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में वृद्धि कर ली थी, तो यह विचारणीय

प्रश्न है क्या क्षमता में वृद्धि के कारण क्षमता उपयोग में गिरावट आयी। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने यदि अपनी क्षमता में वृद्धि नहीं की होती तो इसका वर्ष 2011-12 में उपयोग 48% हो गया होता। अतः, क्षमता उपयोग में गिरावट प्रदर्शित होती यदि घरेलू उद्योग ने क्षमता में वृद्धि नहीं होती।

56. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि घरेलू उद्योग की क्षमता बहुत अधिक है। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि इसकी क्षमता का उपयोग अन्य उत्पादों का उत्पादन करने के लिए भी किया जा रहा है और घरेलू उद्योग ने अपनी ओर से अपने संयंत्र का उपयोग करने का प्रयास किया है और इस कारण ऊपर वर्णित न्यून उपयोग का आशय घरेलू उद्योग की कार्यकुशलता में कमी या घरेलू उद्योग की उच्च निर्धारित लागत से नहीं है।

#### च. मालसूची:

57. चूंकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आ रही है और आयातों में वृद्धि हो रही है इसलिए घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुपात में बिक्री मात्रा में वृद्धि करने में अक्षम रहा और उसे संग्रहित मालसूची की समस्या का सामना करना पड़ा। औसत मालसूची का स्तर वर्ष 2009-10 में घटकर 823 मी.टन रह गया परन्तु उसके बाद इसमें वृद्धि हुई तथा वर्ष 2010-11 में 1,223 मी.टन और वर्ष 2011-12 में 1744 मी.टन हो गया।

वर्ष	अनुक्रमणिका	औसत मालसूची (मी.टन)
2008-09	100	1066
2009-10	77	823
2010-11	115	1223
2011-12	163	1744

#### छ. रोजगार एवं उत्पादकता :

क्षति अवधि के दौरान उत्पादकता और रोजगार के स्तर में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें उक्त अवधि के दौरान सामान्य वृद्धि प्रदर्शित हुई। यह पाया गया कि यह पैरा मीटर कई अन्य पैरामीटरों पर निर्भर है और घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं।

#### ज. कीमत अधोरदन, अधिलंघन/ निग्रहण :

58. यह देखा जा सकता है कि आयातों की उत्तराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। आयात, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध है जिससे उपभोक्ता आयातों की ओर अधिक आकृष्ट हुए हैं। न्यून कीमत पर आयातों के कारण घरेलू उद्योग उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ और निवेशपर अर्जन में गिरावट का

सामना कर रहा है।

59. उत्पादन लागत और बिक्री कीमत की प्रवृत्ति की जांच भी की गई। यह देखा गया कि उत्पादन लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है परन्तु बिक्री कीमत में वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि की तुलना में बहुत कम है।

विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
उत्पादन लागत	सूचीबद्ध	100	87	113	127
बिक्री कीमत	सूचीबद्ध	100	93	120	126

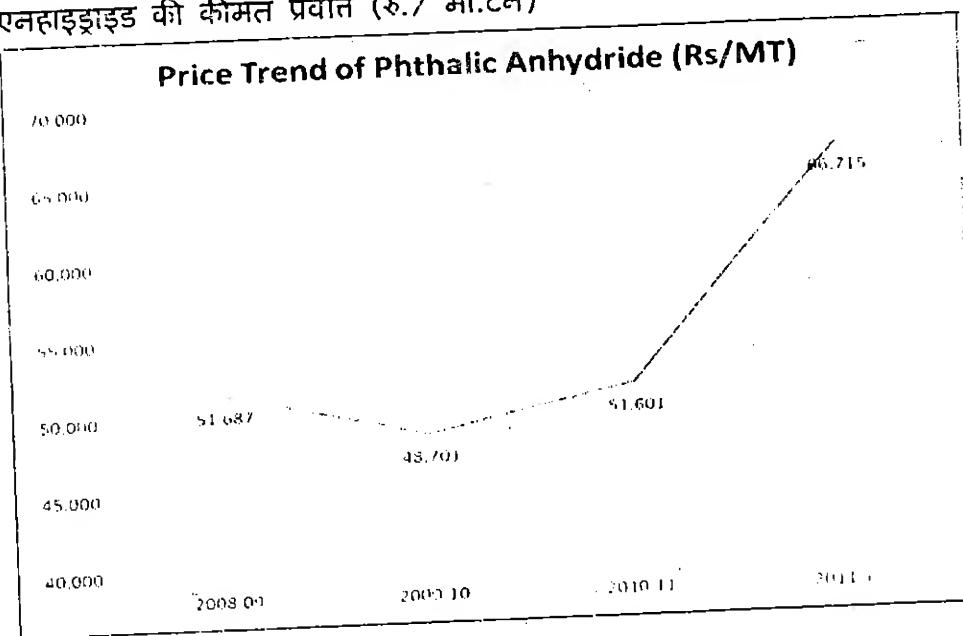
(स्रोत : घरेलू उत्पादन)

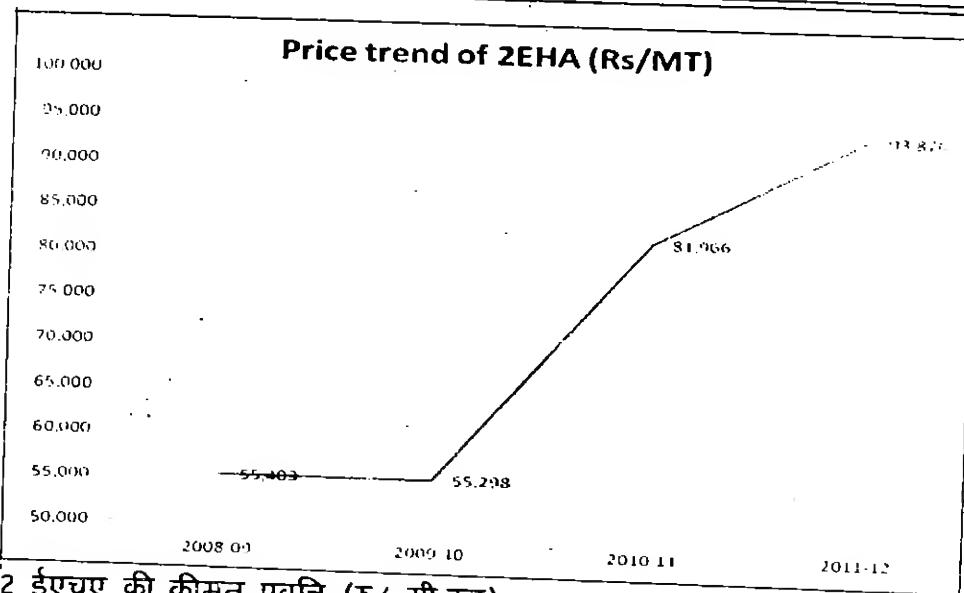
60. उत्पादन लागत में बढ़ोतरी के कारणों की भी जांच की गई। यह नोट किया गया कि डायोक्टायल थैलेट का उत्पादन करने का प्रमुख कच्चा माल थैलिक एनहाइड्राइड (पीएएन) और 2ईएचए है। थैलिक एनहाइड्राइड और 2ईएचए का कीमत उत्तर-चंडाव निम्नलिखित है:

विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
उत्पादन लागत	सूचीबद्ध	100	87	113	127
थैलिक एनहाइड्राइड की कीमत	सूचीबद्ध	100	94	100	129
2ईएचए की कीमत	सूचीबद्ध	100	100	148	169
कुल कच्चे माल की कीमत	सूचीबद्ध	100	98	131	155

(स्रोत : घरेलू उत्पादन)

थैलिक एनहाइड्राइड की कीमत प्रवृत्ति (रु./ मी.टन)





## 2 ईएचए की कीमत प्रवृत्ति (रु/ मी.टन)

61. यह देखा जा सकता है घरेलू उद्योग का उत्पादन सम्पूर्ण क्षति अवधि में प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ वृद्धि हुई। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उत्पादन लागत में वृद्धि कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ोत्तरी हुई।

च. लाभ एवं हानि:

62. घरेलू उद्योग ने एक पैशेवर सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित कर पूर्व लाभ की सूचना दी है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में इस स्थिति तक तीव्र गिरावट आई है कि अब घरेलू उद्योग को घाटा होने लगा है। यह निम्नलिखित से स्पष्ट है:-

विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
लाभ / (हानि)	रु./लाख	***	***	***	***
लाभ/हानि (सूचीबद्ध)	%	(100)	404	509	(210)

(स्रोत: घरेलू उद्योग बनने वाली चार कम्पनियों का प्रमाणित लागत विवरण)

63. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग को वर्ष 2008-09 में उस सीमा तक लाभ अर्जित करने में सक्षम थी जो उन्हें 2010-11 में मिला। तथापि, घरेलू उद्योग को 2011-12 में एक बार फिर काफी वित्तीय घाटा हुआ जिससे सम्बद्धित आयातों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अभी अत्यधिक हाल की अवधि में भी भारी नगदी घाटा हुआ।

64. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग का तुलनपत्र क्षति प्रदर्शित नहीं करता है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के संघटक विभिन्न प्रकार के

प्लास्टीसाइजर्स का निर्माण करते हैं तथा अन्य व्यापारिक गतिविधियों में भी अंतर्गत हैं। वार्षिक रिपोर्ट में केवल डायोक्टायल थैलेट के संबंध में निष्पादन का ही उल्लेख नहीं है और इस कारण वार्षिक रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, डायोक्टायल थैलेट सम्पूर्ण जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कुल कारोबार का 50-60% भाग बना रहा और अतः, तुलनपत्र, जिसमें घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन का उल्लेख किया गया है, पर केवल डायोक्टायल थैलेट के कार्यनिष्पादन के संबंध में भरोसा नहीं किया जा सकता है।

65. गंभीर क्षति के संबंध में निष्कर्ष - विचाराधीन उत्पाद के आयातों में समग्र रूप में तथा भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में भारी वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2008-09 में आयात-यात्रा उच्च थी, जो घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्क के अनुसार वैधिक मंदी के प्रभाव के कारण हुई थी। मंदी का प्रभाव समाप्त हो जाने के उपरांत वर्ष 2009-10 में आयातों की मात्रा में समग्र रूप में तथा उत्पादन एवं खपत दोनों रूपों में गिरावट आई है। तथापि, उसके बाद आयातों में समग्र रूप से एवं भारत में खपत एवं उत्पादन दोनों के संबंध तथापि, उसके बाद आयातों में समग्र रूप के परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर में अत्यधिक वृद्धि हुई। आयातों में अत्यधिक वृद्धि के कारण उत्पादन एवं घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई। उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री और लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में वर्ष 2010-11 तक सुधार हुआ। तथापि, उत्पाद क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री और लाभ में वर्ष 2011-12 में गिरावट आई। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वर्ष 2009-10 में सुधार हुआ और तत्पश्चात उसमें भारी कमी आई। घरेलू उद्योग की मालसूची में वर्ष 2009-10 तक गिरावट आई और तत्पश्चात उसमें वृद्धि हुई। अतः घरेलू उद्योग के हालात पर प्रभाव 10 तक गिरावट आई और तत्पश्चात उसमें वृद्धि हुई। अतः घरेलू उद्योग के बढ़ते आयातों को विचाराधीन उत्पाद के बढ़ते आयातों के कारण गम्भीर क्षति उठानी पड़ी।

#### छ. गम्भीर क्षति की चुनौती

66. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा 6(घ) में निम्नलिखित उपबंध है:

“गम्भीर क्षति की चुनौती” आशय स्पष्ट एवं आसन्न गम्भीर क्षति से है।

67. नियम में निम्नलिखित प्रावधान है-

“यह जांच करने के लिए कि क्या संवर्धित आयातों से प्रदर्शित उद्योग को गम्भीर क्षति हुई है या गम्भीर क्षति हुई है या गम्भीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हुई है, महानिदेशक, उस उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले उद्देश्य परक एवं गणनायोग्य प्रकृति के सभी संगत तथ्यों, खासकर, संबंधित वस्तु के आयातों की दर एवं राशि में संगत रूप

से और संबंधित रूप से मैं वृद्धि, संवर्धित आयातों द्वारा घरेलू बाजार में कब्जाएं गए हिस्से, बिक्री उत्पादन उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ एवं हाजि तथा रोजगार के स्तर में परिवर्तन का मूल्यांकन करेंगे।"

68. यू.एस.—लैम्ब संबंधी पैनल ने विचार किया कि जांच अवधि की समाप्ति से संबंधित अभी हाल ही के उपलब्ध गंभीर क्षति विश्लेषण की भविष्योन्मुखी प्रकृति के संबंध में आंकड़ों पर प्रकाश डालना तर्क संगत था। संगत सार निम्नलिखित है:

‘हमारे विचार से क्षति विश्लेषण की भविष्योन्मुखी प्रकृति के कारण यह तर्कसंगत प्रतीत होगा कि जांच अवधि के प्रारंभ में घटित घटनाएं जांच अवधि की समाप्ति में घटित घटनाओं की तुलना में कम संगत हैं। हालांकि एसजी करार में जांच में विचारित समयावधि को उचित अवधि का निर्धारण नहीं किया गया है, तथापि अर्जेन्टीना-फुटवीयर संबंधी पैनल तथा अपीलीय निकाय दोनों ने इस मुद्दे पर कुछ सीमा तक विचार किया। दोनों ने निष्कर्ष निकाल्य कि (वास्तविक गंभीर क्षति का निष्कर्ष निकालने के लिए) अत्यधिक हाल के आंकड़े सर्वाधिक संगत आंकड़े होंगे। विशेषकर, अपीलीय निकाय ने उल्लेख किया कि संगत जांच अवधि को अभी हाल ही की अवधि में समाप्त नहीं हो जाना चाहिएबल्कि जांच अवधि में अभी हाल ही के विगत को शामिल किया जाना चाहिए।’

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गंभीर क्षति आसन्न महत्वपूर्ण समग्र क्षति से संबंधित है अर्थात् कोई घटना निकट भविष्य में घटित होने वाली है तो वर्तमान गंभीर क्षति निर्धारण की तुलना में क्षति की चुनौती का निर्धारण करने के लिए वही सिद्धांत सत्य माना जाएगा। इससे इस विचार को समर्थन मिलता है कि यू.एसआई टीसी जांच अवधि की समाप्ति से उपलब्ध अत्यधिक अभिनव आंकड़ों पर प्रकाश डालने समय सही था। हम भी यह मानते हैं कि वर्ष 1997 से और अंतरिम 1998 तक की अवधि के आंकड़े उपयुक्त एवं पर्याप्त समावधि को पूरा करते हैं यदि उन्हें मौजूदा प्रवृत्तियों का बहिर्वेशन करते हुए यदि उन्हें मौजूदा प्रवृत्तियों का बहिर्वेशन करते हुए प्रक्षेपणों से सम्पूरित किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह वहीं प्रत्याशित विश्लेषण है जो चुनौती निर्धारण के लिए अपेक्षित है।

अतः हम समझते हैं कि, इसका निर्धारण का आधार सम्पूर्ण जांच अवधि के दौरान की घटनाओं के बजाय जांच अवधि की समाप्ति (अर्थात् एक वर्ष और 9 माह) बनाना अधिक उपयुक्त होगा। यूएस आई टी सी ने इस तथ्य का दैध्य मूल्यांकन करने के लिए कि, अत्यधिक समग्र हाजि निकट भविष्य में “आसन्न” थी, अत्यधिक अभिन्न

आंकड़ों का विश्लेषण किया। इसी टोकेन के द्वारा हम यह भी विचार करते हैं कि भविष्य के विभिन्न उद्योग संकेतकों के लिए अनन्यतः प्रक्षेपणों पर भरोसा करने के बजाए अत्यधिक अभिनव विगत की घटनाओं से संबंधित आंकड़ों को अपने निर्धारण का आधार बनाकर, यूएसआईटीसी ने अपना चुनौती निर्धारण उद्देश्यपरक एवं गणनायोग्य तथ्यों पर, न कि “केवल आरोपो, अनुमान या दूर की संभावना के आधार पर किया है।

69. यूएस-लैम्ब संबंधी पैनल रिपोर्ट, ने एक ऐसे निष्कर्ष में, जिसकी बाद में अपीलीय निकाय ने समीक्षा नहीं की थी, जिसमें इस प्रश्न का समाधान किया गया था कि आयात एक बार बढ़ जाने पर कोई भी क्षति कारित कर सकता है, इसलिए गंभीर क्षति की चुनौती की मौजूदगी का वैध ढंग से निर्धारण करने के लिए आयातों में अतिरिक्त वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। संगत उद्धरण निम्नलिखित है:

“शिकायतकर्ता आगे दावा करते हैं कि अपने क्षति विश्लेषण की रक्षा करने में आयातों में भविष्य में होने वाली प्रत्याशाओं के यू एस संदर्भ “संवर्धित आयातों की चुनौती” तथा गंभीर क्षति की चुनौती दोनों के बराबर बताते हैं, जिसे अर्जेन्टीना-फुटवीयर पैनल ने अनुमेय पाया.....”

हम शिकायतकर्ताओं के इस तर्क से सामान्यतः सहमत हैं कि सम्बद्धित आयातों की चुनौती को गंभीर क्षति की चुनौती के समान नहीं बताया जा सकता है। तथापि, हमारे विचार से, यह वह नहीं है जो यू एस आई टी सी ने अपने मामले में किया है। इसके अतिरिक्त, हम इसे यह भी संभव मानते हैं कि भारी स्तर के लम्बे समय तक चलने वाले आयात जांच अवधि की समाप्ति पर और अधिक बढ़े बिना, यदि रोका नहीं गया तो, वे गंभीर क्षति (अर्थात् गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती) कारित कर सकते हैं। यह कि यदि संवर्धित आयात एक लिखित समय पर गंभीर क्षति से कम क्षति कारित करते हैं तो, य आवश्यक रूप से सच नहीं है कि गंभीर क्षति की चुनौती केवल संवर्धित आयातों अर्थात् अतिरिक्त संवर्धित आयातों से ही कारित की जा सकती है। हमारे विचार से, मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में अभी हाल ही में संवर्धित स्तर तक बढ़े आयातों की निरंतरता ही ऐसी चुनौती कारित करने के लिए पर्याप्त होगी।

70. चीन द्वारा डीओपी के लिए और इसके डाउनस्ट्रीम उत्पाद जैसे पीवीसी के लिए अपनी अत्यावधिक मांग को पूरा करने हेतु अत्यधिक क्षमता सृजन के कारण गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई है।

स्रोत: आई सी आई एस कीमत निर्धारण (थैलिक एनहाइड्राइड) 28 अक्टूबर, 2011

चीन के कान्टिनेन्टल पैट्रोकैमिकल्स (झुहाई) ने झुहाई, चीन में अपने नए एकीकृत पैट्रोकैमिकल सुविधा का निर्माण कार्य पुनः शुरू कर दिया है, जैसा कि कम्पनी के एक घनिष्ठ स्रोत ने मंगलवार को बताया। इस परिसर में प्रतिवर्ष 120,000 टन की क्षमता का डीओपी संयंत्र और एक 80,000 टन/प्रति वर्ष पीए संयंत्र होगा।

ताईवान का यूपीसी टेक्टनोलाजी कार्य चीन के लियाओनिंग प्रांत में लियाओयांग में एक नया पैट्रोकैमिकल परिसर जुलाई, 2013 के मध्य तक शुरू करने जा रहा है, कम्पनी के एक स्रोत ने मंगलवार को बताया। यूपीसी इस परिसर का निर्माण करना अगले वर्ष के प्रारंभ में शुरू कर देगा, कम्पनी के एक सूचना स्रोत ने बताया। इस परिसर में 140,000 टन/प्रतिवर्ष की क्षमता का एक संयंत्र तथा 240,000 टन/प्रतिवर्ष डीओपी संयंत्र होगा।

स्रोत: आईसीआईसी कीमत निर्धारण (थैलिक एनहाइड्राइड) 2 दिसम्बर, 2011

ताईवान का नान या प्लास्टिक्स अपनी कुल पीए प्रचालन दर दिसम्बर के मध्य तक 100% की क्षमता तक लाने का विचार कर रहा है क्योंकि कम्पनी को उम्मीद है कि चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से पीए की मांग में इस वर्ष के अंत तक इजाफा होगा, कम्पनी के एक स्रोत ने शुक्रवार को बताया।

इसी स्रोत ने आगे उल्लेख किया कि पीए के लिए नान या की मांग तब बढ़ेगी जब यह उसी स्थल पर 5 दिसम्बर को अपनी डायोक्टायल थैलेट (डीओपी) क्षमता 400,000 टन/प्रति वर्ष को पुनः शुरू कर देगा।

71. इसके अतिरिक्त, डीओपी बाजार में थाईलैंड में आई बाढ़ का पर्याप्त प्रभाव रहा है जिसने देश की क्रय प्रवृत्ति को शूल्य स्तर तक लाकर खड़ा दिया। इससे चीन की मालसूची का विपर्थन अन्य संभावित बाजारों को हुआ। यह स्थिति कोरिया ताईवान के उत्पाकों की पहले से ही मौजूद क्षमता के अनुरूप बनी रही जो कभी डीओपी के चीन के प्रमुख निर्यातक थे। वास्तव में, ताईवान का एक उत्पादक अपनी निर्माणाधीन सुविधा को जुलाई, 2013 में पुनः शुरू करने की प्रक्रिया में है जिसके थैलिक एन हाइड्राइड संयंत्र की क्षमता 140,000 टन प्रतिवर्ष तथा डीओपी संयंत्र की क्षमता 240,000 टन/प्रतिवर्ष होगी।

आई सी आई एस कीमत निर्धारण (थैलिक एनहाइड्राइड) 9 दिसम्बर, 2011

थाईलैंड में क्रेता केवल जरूरत आधार पर क्रय कर रहे हैं क्योंकि उनके अधिकांश संयंत्र अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर रहे हैं।

आईसीआईएस कीमत निर्धारण (थैलिक एनहाइड्राइड) 16 दिसम्बर, 2011

थाईलैंड में क्रय में रुचि कम ही है क्योंकि देश अभी भी अपनी फैक्टरियों से बाड़ का पानी निकालने से जूझ रहा है।

72. ये आयात भारत की बाजार में संवर्धित मात्रा में समग्र रूप में तथा भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में दोनों तरह से प्रवेश कर रहे हैं। घरेलू एवं आयातित उत्पाद दोनों के बीच अत्यधिक कीमत अंतर से संवर्धित आयातों का घरेलू उद्योग की कीमत पर पर्याप्त विपरीत प्रभाव डालता है। संबंद्ध वस्तु के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत पर विचार करते हुए, घरेलू एवं आयातित वस्तु के बीच कीमत अंतर काफी अधिक है और इसके बने रहने की संभावना है जिससे आयात अधिक आकर्षक होंगे और घरेलू उद्योग को क्षति संभावना बनी रहेगी।

ट.क्षति के अन्य कारक:

73. सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 8 के अनुबंध के पैरा (2) निर्धारित करता है कि उप-पैराग्राफ (1) में उल्लिखित निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि, उद्देश्य परक साक्ष्य के आधार पर जांच संबंधित वस्तु के संवर्धित आयातों तथा गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कारणात्मक सम्पर्क स्थापित नहीं करती है। यदि आयातों के अतिरिक्त अन्य तथ्य घरेलू उद्योग को 'गंभीर क्षति' के लिए संबंधित आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इस कारण घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर सकने वाले अन्य सम्भावित तथ्यों की जांच भी की गई।

74. इस संबंध में निम्नलिखित संगत तथ्य हैं—

- क) उत्पाद की मांग: हालांकि समग्र मांग में वृद्धि हुई है फिर भी आयात की मात्रा महत्वपूर्ण बनी रही। वास्तव में, यह नोट किया जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग और घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में समग्र रूप से गिरावट आई है, परन्तु आयातों का हिस्सा बढ़ा है। इस प्रकार यह स्पष्टतः देखा जा सकता है कि संवर्धित आयातों से मांग में बढ़े हुए हिस्से में कमी आई है।
- ख) खपत की प्रणाली में परिवर्तन: विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं आया है। खपत की प्रणाली में परिवर्तन को घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- ग) व्यापार प्रगितबंधात्मक प्रक्रियाये तथा विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रति स्पर्धा: ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाये नहीं है जिन्हें घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

घ) निर्यात निष्पादन: आवेदकों ने विचाराधीन उत्पद की अल्पमात्रा का निर्यात किया है। तथापि, घरेलू उद्योग को दावाकृत क्षति घरेलू प्रचालनों के कारण हुई। आवेदकों ने घरेलू प्रचालनों के लिए लागत एवं क्षति के लिए निर्यातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

इ) तकनीक में विकास: उत्पाद के उत्पादन के लिए तकनीक में कोई खास अंतर नहीं आया है। अतः तकनीक में विकास क्षति के लिए उत्तरदायी तथ्य नहीं है।

75. अतः, यह नोट किया जाता है कि सम्भावित अन्य तथ्यों ने घरेलू उद्योग की क्षति कारित नहीं की है।

झ. संवर्धित आयात एवं गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के लिए चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध :

76. पैरामीटरों का ऊपर वर्णित के अनुरूप व्यापक मूल्यांकन यह प्रदर्शित करता है कि गंभीर क्षति की चुनौती संवर्धित आयातों के कारण हो रही है। कारणात्मक संबंध का निर्धारण करने के लिए उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले उद्देश्य परक एवं गणनात्मक प्रकृति के सभी संगत तथ्यों का मूल्यांकन किया गया। प्रस्तुत मामले में आयातित वस्तु घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध है। उपभेदताओं का झुकाव आयातित वस्तुत की ओर बढ़ रहा है, इससे घरेलू उद्योग को उप-इष्टतम कीमत पर अपना सामान बेचने को मजबूर होना पड़ा रहा है। घरेलू उद्योग की बिक्री कम हो रही है और मालसूची में वृद्धि हो रही है। संवर्धित आयातों के कारण उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ, निवेश पर अर्जन सभी में गिरावट आई है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन हो रहा है। परिणामस्वरूप, अतः घरेलू उद्योग को लाभ निवेश से अर्जन में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। अतः यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को संवर्धित आयातों के कारण गंभीर क्षति हुई है।

#### झ. जन हित:

77. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 3 में निम्नलिखित का उल्लेख है:

1. कोई सदस्य रक्षोपाय साधन का उपयोग, विगतमें स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसरण में सक्ष प्राधिकारियों द्वारा जांच करके कर सकता है तथा उसे गाट 1994 के अनुच्छेद X के अनुरूप सार्वजनिक कर सकता है। इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपयुक्त सार्वजनिक सूचना दी जाएगी तथा सार्वजनिक सुनवाई एवं किसी अन्य ऐसे समुचित साधन का उपयोग किया जाएगा जिसमें आयातक, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें तथा अपने विचार व्यक्त कर सकें, इसके अलावा, अन्य पक्षकारों द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरणों का उन्हें उत्तर देने का अवसर मिल सके तथा वे अपने विचार प्रस्तुत कर सकें, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह होगा कि रक्षोपाय साधन का उपयोग करना

जनहित में है या नहीं। सक्षम प्राधिकारी एक रिपोर्ट प्रकाशित करेगे जिसमें उनके निष्कर्ष का उल्लेख होता है और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संबंधित मुद्दे के तथ्यों तथा विधि का उल्लेख होगा।

78. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण विभिन्न पण्धारियों को भिन्न ढंग से प्रभावित कर सकता है और हो सकता है कि यह प्रभाव विभिन्न आर्थिक पण्धारियों के लिए प्रतिस्पर्धी हितों के कारण स्वैतंत्र्य उपर्युक्त न हो। अतः विभिन्न आर्थिक पण्धारी समूहों के हितों का विश्लेषण उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया गया है।

79. एलसीपीएम ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किया है:

क) डीओपी का प्रमुख प्रयोक्ता होने के कारण, एलसीपीएम सदस्य, यदि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो, सर्वाधिक पीड़ित पक्षकार होंगे क्योंकि उनके उत्पाद को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। अतः रक्षोपाय शुल्क यदि जनहित के विरुद्ध है तो, उसका अधिरोपण नहीं किया जाना चाहिए।

ख) एलसीपीएमए के सदस्य घरेलू उद्योग भी हैं और उनहें अपनी परिष्कृत वस्तु का आयात करने के लिए प्रतिस्पर्धा हेतु स्पष्ट नीति की आवश्यकता होती है। उनके उत्पाद के लिए कोई अतिरिक्त संरक्षण प्राप्त नहीं है। विदेश स्थित चमड़े के कपड़ों का अग्रणी उत्पादक अपना माल भारत में निर्यात करने के उत्सुक हैं।

ग) चूंकि राज्य के सभी कार्य व्यापक जनहित में किए जाते हैं, इसलिए राज्य प्राधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे जनहित के मुद्दे की जांच करें।

80. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किया है:

क) प्लास्टीसाइजर उपभोक्ता उद्योग ऐसा है जो इसकी बढ़ी हुई लागत को अपना डाउनस्ट्रीम उत्पाद की लागत में समाहित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, 20% रक्षोपाय शुल्क का प्रयोग इसके 3 प्रमुख प्रयोक्ताओं पर न्यून होगा क्योंकि उसका चर्म वस्त्रों पर प्रभाव केवल 0.29% है। कापर केबल्स पर 0.02% और पीवीसी फ्लोमिसबल पाइप्स पर 0.43% है जो बिल्कुल नगण्य है।

ख) डीओपी को शून्य सीमा शुल्क संरक्षण प्राप्त है। विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले दो प्रमुख कच्चे माल थैलिक एनहाइड्राइड और 2 ईएचए पर भी उसी स्तर की सीमा शुल्क है, जबकि इन दोनों कच्चे पदार्थों, थैलिक एनहाइड्राइड और ईएचए को क्रमशः 2.5% शुल्क संरक्षण है।

ग) पिछले दशक में कई उत्पादकों ने अपने प्रचालन पहले ही बंद कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त, यदि घरेलू उद्योग को क्षति बनी रहती है तो इससे बाकी घरेलू उत्पादक भी अपना काम बंद कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 'डीओपी' जैसे एक

महत्वपूर्ण रसायन का देश में उत्पादन नहीं होगा और तदद्वारा 'डीओपी' के प्रयोक्ता पूरी तरह से आयातों पर निर्भर हो जाएंगे।

81. यह देखा जाता के कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत बिक्री लागत की तुलना में बहुत अधिक कम है। डीओपी उद्योग की वर्तमान लाभप्रदायकता पर विचार करते हुए रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण न करने से डीओपी उद्योग बिल्कुल बंद हो सकता है। डायोकटायल थेलेट के उत्पादों को, किसी भी तरह से, कोई शुल्क संरक्षण प्राप्त नहीं है, जिसके कारण यह स्पष्ट है कि विगत में कई उत्पादकों ने अपने प्रचालन बंद कर दिए हैं और उपभोक्ताओं पर रक्षोपाय शुल्क का मिनिमल प्रभाव है, इसलिए यह नोट किया जाता है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में होगा।

82. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में होगा क्योंकि इससे न केवल घरेलू उद्योग की क्षति कम होगी बल्कि इससे घरेलू उद्योग में होने वाली गिरावट को रोका जा सकता है।

83. घरेलू उद्योग ने 20% रक्षोपाय शुल्क के प्रभाव का प्रासंगिक डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर आकलन किया है। यह पाया गया कि रक्षोपाय शुल्क लगाने से कीमत में 20% वृद्धि का यदि प्रासंगिक अंतिम उत्पाद (यह मानते हुए कि घरेलू उद्योग की कीमतों में 20% वृद्धि करेगा) में जोड़ा जाए तो प्रासंगिक अंतिम उत्पाद पर इसका न्यूनतम प्रभाव होगा, जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है:

- क. चमकड़े के वस्त्र 0.29%,
- ख. तांबे के तार 0.02%
- ग. पीवीसी फ्लेकिसबिल पाइप 0.43%.

84. घरेलू उद्योग के उपर्युक्त दावे का मौखिक सुनवाई में मौजूद उपभोक्ता एसोसिएशन या अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विरोध नहीं किया। और न ही किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रस्तुतिकरण में इसके विपरीत कोई अन्य गणनात्मक दावा नहीं किया गया है। यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कीमतों में 20% वृद्धि हो जाने के बावजूद प्रासंगिक अंतिम उत्पाद पर उसका प्रभाव बिल्कुल भी विपरीत नहीं होगा। रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के परिणामस्वरूप प्रासंगिक अंतिम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि नहीं होगी।

85. रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आलोक में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में होगा और अंतिम प्रयोक्ताओं के हितों पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## ट. समायोजन योजना :

ट. समायोजन योजना :  
86. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने ऐसी अर्थक्षम समायोजन योजना प्रस्तुत नहीं की है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके। आवेदकों ने समयोजन योजना अपने आवेदन पत्र तथा उत्तरवर्ती लिखित प्रस्तुतिकरणों में प्रस्तुत की है।

87. रक्षोपाय नियमावली 1997 के नियम 5(2) में "आयायत प्रतिस्पर्धा का सकारात्मक समायोजन करने के लिए किए जा रहे प्रयासों या की जाने वाली योजना या दोनों" के संबंध में एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। रक्षोपाय संबंधी डब्लू टी ओ करार में प्रावधान है कि कोई सदस्य रक्षोपाय साधन गंभीर क्षति को रोकने या उसका समाधान करने और समायोजन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक सीमा तक ही कर सकता है।

88. निर्णायक रक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को अल्पावधि सीमा तक के लिए पुनर्गठन करने तक का प्रावधान करना है ताकि वह आयातों के साथ अधिक प्रभावकारी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकें। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख (4) तथा रक्षोपाय नियमावली, 1997 के नियम 16(2) में, यदि इस तथ्य के कोई साक्ष्य नहीं है कि घरेलू उत्पादक समायोजन कर रहे हैं तो साधन की सम्भावित सीमा को निषेध किया गया है।

89. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई गई समायोजन योजनाएं निम्नलिखित हैं, जिनमें अनिवार्यतः निम्नलिखित शामिल हैं:

क. प्रक्रिया जारी रखने के लिए बैच प्रक्रिया

## ख. संयंत्रों का आटोमेशन

ग. अपशिष्ट रिकवरी

### घ. ऊर्जा लागत कम करना

डॉ. आई.टी का प्रयोग कर रहे संयंत्रों की कड़ी मानिटरिंग

### च. प्रशासनिक व्यय में कमी

## छ. प्रभावकारी मालसूची प्रबंधन

ज. इलेक्ट्रिकल उपकरणों का आधुनिकीकरण करके विद्युत व्यवस्था

### झ. बेहतर विनिर्माण प्रक्रियाओं का प्रयोग

## अ. प्रबंध प्रक्रियाओं में सुधार

## घरेल उद्योग द्वारा प्रस्तुत पुनर्ग

90. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पुनर्गठन योजना में लागत में कमी और मौजूदा उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने पर प्रकाश डाला गया है यह नोट किया जाता है घरेलू

उद्योग की समायोजन योजना तकसंगत अर्थक्षम एवं व्यवहार्य हैं जिन्हें कार्यान्वित किया जा सकता है।

91. पुनः यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने उर्जा लागत, प्रशासनिक उपरिशीर्ष और अन्य अंतरण लागत आदि के रूप में लागत कटौती करने के प्रयास पहले ही शुरू कर दिए हैं जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हैः—

विवरण	यनिट	2009-10	2010-11	2011-12
उत्पादन लागत	रु./मी.टन	100	130	146
कच्चे माल की कुल लागत	रु./मी.टन	100	134	159
उपरिशीर्ष परिवर्तन लागत	रु./मी.टन	100	111	89

92. उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की उपरिशीर्ष लागत में अभी हाल ही की अवधि अर्थात् 2011-12 में कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद गिरावट आई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उद्योग ने अभी हाल ही की अवधि में प्रचालन मानदंडों में प्रभावी सुधार करने के प्रयास किए हैं।

#### ठ. विकासशील राष्ट्र :

93. विकासशील राष्ट्रों से आयातों की प्रतिशतता की भी जांच की गई। मलेशिया, जिसका भारत को वित्त वर्ष 2010-11 और वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान कुल आयातों का 16.72% आयात हुआ है के सिवाय अन्य विकासशील देशों का भारत में कुल आयातों का व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से क्रमशः 3% और 9% से कम एवं आयात हुआ है। अतः, मलेशिया को छोड़कर अन्य विकासशील राष्ट्रों के मूल के विचाराधीन उत्पाद के आयात, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के परंतुक में दिया गया सीमा शुल्क आकर्षित करते हैं।

#### ड. निष्कर्ष

94. उपर्युक्त परिणामों के मद्देनजर, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि डायोक्टायल थैलेट के भारत में संवर्धित आयातों ने डायोक्टायल थैलेट के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति कारित की है या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर दी है और भारत में डायोक्टायल थैलेट के आयातों पर सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और उसका आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 12 में दी गई शर्तों के अनुरूप रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना जनहित में होगा। इस अवधि को, घरेलू उद्योग के हित का संरक्षण करने के लिए व्यूनतम अवधि के रूप में माना गया है। इसके अतिरिक्त, परिकलित रक्षोपाय शुल्क का अधोगामी नियमन किया गया है जिससे अंतिम उपभोक्ताओं का हित बनाए रखने के लिए घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा कायम रखने हेतु आयातों की अनुमति दी जा सके। घरेलू उत्पादकों ने लगाई गई पूँजी पर

प्रत्याशित अर्जन के आधार पर लाभ की निश्चित राशि का दावा किया है जिसे उच्च माना गया और अतः उत्पादन की भारित औसत लागत के आधार पर लाभ (गोपनीय) की न्यूनतर राशि पर समुचित रूप से विचार किया गया है और उसकी अनुमति दे दी गई है। अतः उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर यह देखा जाता है कि –

क) विचाराधीन उत्पाद का आयात क्षति अवधि में समग्र रूप से बढ़ा है, जबकि अभी हाल ही की अवधि में आयातों में तीव्र वृद्धि हुई है,

ख) विभिन्न देशों से डीओपी (डायोक्टायल थैलेट) के संवर्धित आयातों से घरेलू उद्योग/डीओपी के उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है और गंभीर क्षति कारित होने की चुनौती उत्पन्न हो गयी है; और

ग) यह स्पष्ट हो गया है कि घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों जैसे उत्पादन, बिक्री, माल सूची को डीओपी के संवर्धित आयातों के कारण क्षति हुई है;

घ) इसी ओपी के सभी देशों, और भलेशिया के अलावा अन्य विकाशील राष्ट्रोंके मूल के विचाराधीन उत्पाद को छोड़कर आयातों पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के परन्तुक में दी गई शर्तों के अनुरूप रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना जन हित में होगा।

#### ट. सिफारिश

95. सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 12 के अनुरूप घरेलू उत्पादकों द्वारा डायोक्टायल थैलेट की औसत उत्पादन लागत, लगाई गई पूंजी पर युक्ति संगत अर्जन की अनुमति देकर, पर विचार करते हुए, डायोक्टायल थैलेट, एक कार्बनिक यौगिक, जिसका संक्षिप्तीकरण डीओपी है, जिसे बीआईएस (2-इथायल हेक्साइल)थैलेट, जिसका सामान्यतः संक्षिप्त नाम डीईएचपी है, एक कार्बनिक यौगिक जिसका फार्मूला सी6एच4(सी8एच17सीओओ)2 है और जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत अध्याय शीर्षक 29173920 के अंतर्गत आता है, के सभी आयातों पर रक्षोपाय शुल्क निम्नलिखित ढंग से अधिरोपित करने की एतद्वारा सिफारिश की जाती है:

अवधि	रक्षोपाय शुल्क की दर
प्रथम वर्ष	15%
द्वितीय वर्ष	10%

उपर्युक्त रक्षोपाय शुल्क जो इन वस्तुओं के आयात पर गैर-विभेदकारी आधार पर लगाए जाने की सिफारिश करना घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए न्यूनतम माना जाता है।

तथापि, चूंकि मलेशिया के सिवाय अन्य किसी भी विकासशील राष्ट्र से आयात में व्यक्तिगत रूप से 3% और सामूहिक रूप से 9% से अधिक वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद पर, मलेशिया को छोड़कर अन्य विकासशील राष्ट्रों के मूल के आयातों पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के परन्तुक में दी गई शर्तों के अनुरूप रक्षोपाय शुल्क आकर्षित नहीं करता है।

[फा. सं. डी-22011/13/2011/पार्ट ए]

इंद्राणी दत मजूमदार, महानिदेशक

**DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS**

**(Customs and Central Excise)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th November, 2012

**Subject : Safeguard investigation concerning imports of Dioctyl Phthalate (DOP)—Final findings under Rule 11 of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997.**

**G.S.R. 828(E).**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and Rule 11 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 thereof;

**A. Procedure**

1. An application was filed under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 [hereinafter referred to as "Safeguard Rules"] by (a) KLJ Plasticizers Limited, (b) Payal Polyplast Pvt Ltd (c) PCL Oil & Solvent Ltd and (d) N.K. Polymers & Additives Mfg .Co, seeking imposition of Safeguard Duty on imports of Dioctyl Phthalate (hereinafter referred to as DOP) into India alleging that increased imports of Dioctyl Phthalate was causing and/or threatening to cause serious injury to the domestic producers of Dioctyl Phthalate in India. The Notice of Initiation of safeguard investigation concerning imports of Dioctyl Phthalate into India was issued on 23<sup>rd</sup> May, 2012 and was published in the Gazette of India Extraordinary on the same day vide GSR 383(E).
2. A copy of the Notice of Initiation dated 23<sup>rd</sup> May, 2012 along with copy of non-confidential version of the application filed by the Domestic Industry were forwarded to the Central Government, in the Ministry of Commerce and other ministries concerned, Govts of exporting countries through their Embassies/ High Commission in New Delhi and all known interested parties listed below in accordance with Rule 6(2) and 6(3) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty) Rules, 1997:

**Domestic Producers**

- a. KLJ Plasticizers Limited,
- b. Payal Polyplast Pvt Ltd.
- c. PCL Oil & Solvent Ltd.
- d. N.K. Polymers & Additives Mfg.CO

**Importers/users**

- a. Alpha Polymers, Alpha Nagar, Nagar Mala, Adivaram 1 Alagapuram 636 016
- b. Anukampa Polymers & Technologies Pvt. Ltd., B-21 Industrial Estate, Sanathnagar, HYDERABAD-500018, A.P.
- c. Gloster Cables Limited, 310/E, NH 7, Kallakal Village, Toopran Mandal Medak District A.P.
- d. Prime Polymers, No. 18, Lal Bagh Road, Bangalore 560027, Karnataka
- e. S. Gopal Kamath (Cochin), No. 39/330A, Arangath Road, P. Box No. 2021, Emakulam, Cochin 682018
- f. Coir Tuft International Pvt. Ltd., Plot No.49 (Site-A), Rubber Park, Irapuram Village, Kannathunadu Taluk, Perumbavoor
- g. Kerafibertex Intl. Pvt. Ltd; Plot No. 53-57, Kintra (EP1P), Kusumagiri, Kakkanad, Kerala
- h. The Alleppey Company, 14/385 A, Puthanangadi, Muhamma 688525, Kerala
- i. Kerala Balers (P) Ltd., A.S. Road, Alleppey, Alleppey 688007, Kerala.
- j. Tube Products Mahadevapura, White Field Road, Bangalore 560048, Karnataka
- k. Gee Tee (India) Ahmedabad, Bharat Cement Pipe Compound, Narol Circle, Narol, Ahmedabad 382405, Gujarat
- l. Nishan Marketing B-204, Krishna Complex, Opp. Rajpath Club, Off S.G. Road, Ahmedabad 380054, Gujarat
- m. Sigma Organics of Chemicals Pvt. Ltd, Sajjan House, 7 New Agarwal Nagar, Opp. Lotus Navlakha, Indore 452001
- n. Laser Cables Pvt. Ltd PO Biprannapara, Jalan Indl. Complex, Jangapur, Howrah 711411, West Bengal
- o. Plasti Pack, 115, College Street, Unit-3E, 3<sup>rd</sup> Floor Kolkata, West Bengal
- p. Jain Chemical (Jaipur) F-542, Road No. 1, DVKI Area Jaipur 302004, Rajasthan
- q. Jain Chemical & Plastic (Delhi) 3545/5, Jai Mata Market, Tri Nagar New Delhi – 1100 35
- r. Leo Vinyls, Kapurthala Road Jalandhar Punjab
- s. Jainco Enterprises, Jain Building, Basti Bawa Khel Kapurthala Road, Jalandhar – 144021, Punjab
- t. Arvind Plastic Udyog, A-55, Giriraj Indl. Estate, Mahakali Caves Road, Andheri (E), Mumbai
- u. Radha Plastic Inds. (Daman) 48/2, Daman Indl. Estate, Kadaiya Nani Daman
- v. Varun Organics Pvt. Ltd, 101, Sujata Chamber, 1/3, A.B. Gandhi Marg Masjid Bundar, Mumbai 400009

- w. Krishna Enterprises Shop No. 3, Kamal Mohan Hsg. Society, 126 Nana Peth, Pune 411002
- x. A.D. Industries, B-4, Giriraj Estate, Mahakali Caves Road, Andheri (E), Mumbai
- y. Diamond Pipes & Tubes Pvt. Ltd, No. 50, 7<sup>th</sup> Cross, Wilson Garden, Bangalore 560027, Karnataka
- z. BDS Industries, Survey 70/2 (B), Daman Indl. Est. Kadaiya, Daman
- aa. Poonam International, 195/2, Chikkanahalli Road, Bommanahalli, Bangalore 560068
- bb. Royal Cushion Vinyl Products Ltd, Plot No. 55, Village, Garadhia, Taluka, Sayli, Distt Baroda, Gujarat
- cc. Viny Royal Plasticcoats Ltd, Plot No. 319, Baroda, Godhra Road, Baska Village Halol, Panchmahal

### Exporters

- a. M/s. BASF Petronas Chemicals, SDN B DC 802, Central Tower, Wisma Consplant 1, Jalan SS16/4, Subang Jaya, 47500, Malaysia
- b. Chemcross Inc, Aisa, Yongsei Bldg; 4<sup>th</sup> Floor, Namdaeun Road, 5-KA, Chung-Ku, Seoul, South Korea
- c. Humade Corporation, Room No. 1505, Master Tower B/D 553, Dowha Dong, Mapo Gu, Seoul, 121-743, South Korea
- d. M/s Woori Pand Corporation, Rm. 905, Olympia Bldg. No. 196, Jamsilb On Dorg Sorgpa Gu, Seoul, South Korea
- e. The Normandy Group, S.A., Temple Financial Centre, P.O. Box 228, Leeward Highway, Providenciales, Turks and Caicos Islands, British West Indies, Netherlands
- f. Gulf Resources Development Corporation, P.O. Box 61283, Jabel Ali, Dubai, U.A.E.
- g. Petrochem Middle East FZE, P.O. Box 17028, Jabel Ali, Dubai, U.A.E.
- h. KASB Petroleum FZ Co., P.O. Box 117280, Dubai, U.A.E.
- i. UPC Technology Corporation, 5F, 20, Lane 478, Rueiguang Rd, Neihu Chiu, Taipei, Taiwan
- j. Continental Chemical Corp. PTE Ltd., 2 Seraya Plaza, Jurong Island, Singapore – 6277857
- k. Dinowic PTC Ltd, 5 Shenton Way, 19-08 UIC Building, Singapore – 068808
- l. Nimar Chemicals Pakistan Limited, 51-N Industrial Area, Gulmarg II, Lahore, Pakistan
- m. ICC Chemical Corporation, 460 Park Avenue, New York, NY, USA

n. Vinmar Overseas Ltd, 16800 Imperial Valley Drive, Suite 499, Houston, TX 77060

o. Everest Polymers Pvt Ltd, P.O. Box No. 47, Makawanpur, Nepal

p. Farabi Petrochemicals Co., No. 35/2 North Gadi Ave., Sanei Alley, Tehran – Iran

#### Exporting Nations:

- a. The Republic of Korea, through their Embassy in New Delhi.
- b. Taiwan, through their Embassy in New Delhi.
- c. Malaysia through their High Commission in New Delhi.
- 3. Questionnaires were also sent, on the same day, to all known domestic producers and importers and exporters and they were asked to submit their response within 30 days.
- 4. Requests to consider them as *interested parties* and extension of time were received from the following parties. After taking into account the time limits for completing the investigation within the prescribed period, requests for extension of time to submit reply as per Rule 6(4) of Safeguard Rules were allowed, as prayed for.

#### Exporters

- i. M/s LG Chem Ltd., Korea through their lawyer M/s WTC Consultants.
- ii. M/s Nan Ya Plastics Corp, Taiwan.

#### Users

- i. M/s Leather Cloth and Plastics Manufacturers Association (M/s LCPMA), New Delhi.

- 5. The Govt. of Mexico through their embassy, M/s Gee Tee India and M/s Nishan Marketing had requested for removing their names from the list of interested parties due to the reason that they were not exporting/importing Dioctyl Phthalate(DOP) at all. Their requests were also acceded to.
- 6. The information presented by the applicants was verified by onsite visits to the plants of the domestic producers to the extent considered necessary. The non confidential version of verification report is kept in the public file.
- 7. All the views expressed by the interested parties have been taken into account in making appropriate determination. The non confidential information received or acquired has been kept in the public file.

- 8. A public hearing was held on 25<sup>th</sup> September, 2012, notice for which was sent on 20<sup>th</sup> September, 2012. All interested parties who participated in the public hearing were requested to file a written submission of the views presented orally in terms of sub rule (6) of rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by 1<sup>st</sup>

October, 2012. Copy of written submissions filed by one interested party was made available to all the other interested parties. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other interested parties by 4<sup>th</sup> October, 2012. All the views expressed by the interested parties either in the written submissions or in the rejoinders were examined and have been taken into account in making appropriate determination. The Govt. of Taiwan and the Govt. of Republic of Korea filed post hearing written submissions through emails dated 25/9/12 and 1/10/12 respectively with no hard copies filed. M/s LCPMA also filed hard copy of post hearing written submissions on 5/10/12. M/s LCPMA also filed hard copy of post hearing rejoinder submissions on 5/10/12, i.e. after the due date. However, all these procedural lapse/delay have been considered and are condoned.

9. All the views expressed by the interested parties and other domestic producers either in the written submissions or in the rejoinders and response to the domestic industry submissions were examined and have been taken into account in making appropriate determination.

#### B. Views of Domestic industry

a. The petitioners constitute domestic industry as per Customs Tariff Act' 75 as they constitute the major proportion in the total Indian production of DOP as per the table below.

SN	Year	Petitioner (%)	Other Indian Producers (%)	All Indian Producers (%)
1	2009-10	94	6	100
2	2010-11	91	9	100
3	2011-12	91	9	100

b. The information for the year 2008-09 has to be ignored in view of recession in this period. Otherwise, while analyzing data from 2008-09, it would be required to be kept in mind that 2008-09 was a period in which domestic industry was suffering due to recession and hence all parameters would show improvement if compared to the subsequent years.

c. There has been a sudden, sharp and significant increase in imports within the meaning of safeguard rules and the decisions of Argentina footwear case and US Line Pipe case.

d. The imports in relation to the production and consumption have increased throughout the period as well as in the recent period.

e. Increase in imports is due to the following reasons:

- Setting up of new Phthalic Anhydride plants by Chinese producers and resultant surplus capacities in Phthalic Anhydride in third countries, leading to diversion of Phthalic Anhydride production to DOP
- Sluggish demand in China for Phthalic Anhydride, leading to diversion of Phthalic Anhydride production to DOP

- iii. Slowdown in the end markets of Europe and America
- iv. Restriction in usage of DOP in Europe
- v. Growing demand of the product under consideration in India.

Due to the above listed factors, the exporters from Korea and Taiwan were compelled to search for the growing market for their product and India being the most viable choice was targeted, leading to increased imports in India.

- f. Increased imports have adversely impacted the production and capacity utilization of domestic industry.
- g. The sales of the domestic industry increased till 2010-11 but declined during the recent period, whereas the imports have surged.
- h. Domestic industry is facing the problem of accumulated inventories due to decline in market share affecting production and capacity utilization.
- i. In order to sustain in the market, the domestic industry has to reduce its prices far lower than the cost of sales thereby suffering significant losses. At the same time, the profitability and consequently cash profits and return on investment have started declining in the most recent period, which had actually improved previously.
- j. Threat of serious injury is established by following factors.
  - i. The price difference between domestic and imported product is significant;
  - ii. The foreign producers are holding significant unutilized capacities. Resultantly, the foreign producers are looking for additional markets to the extent possible;
  - iii. The major Chinese market has clogged for the export oriented producers of Korea and Taiwan, whereas the Indian market is quite strong;
  - iv. There has been restriction in usage of DOP in Europe worsened by the crisis in Europe. Due to such restriction, the producers/exporters started looking for new markets for their products and India with its growing demand offered a better opportunity for them to export which has led to increase in imports from such countries and also pose a threat of further increase in imports.
- k. Since there is negligible impact on the eventual end product and considering that the survival of the domestic industry is must, the imposition of safeguard shall be in public interest.

### C. Views of Exporting Nations

#### Government of Korea

- a. Data for 2011-12 are described as annualized, leading to high misrepresentation. This can be seen from the fact that in the first quarter of 2012, Korea's exports dropped to 3382 MT from 11924 MT in the same period in 2011.

- b. The volume of imports fell steeply from 2008-09 to 2009-10, rose slightly in 2010-11 and data for 2011-12 is unclear. Hence the petitioners claim that there is sudden, sharp and significant increase in imports is not substantiated by data.
- c. No unforeseen circumstances have been demonstrated, as Korea hardly exported the products to Europe and hence the Europe crisis barely influenced exports to India.
- d. Production, capacity and capacity utilization have all shown increasing trends and hence there is no injury to domestic industry. The trend in domestic industry shows no signs of the "serious injury" as described in Article 4 of the Safeguard Agreement.
- e. Any alleged injury to domestic industry is due to safeguard duty on Phthalic Anhydride and hence no causal link.

#### Government of Taiwan

- a. One of Taiwan's exporters got several orders from Indian customers in 2010-11 due to local supply shortage of DOP in India. After this period exports to India dropped.
- b. Domestic demand for DOP in India has exceeded production and thus import of DOP is only to fulfill needs of Indian consumption.

#### D. Views of Importers/ Users

##### M/s. Leather Cloth and Plastics Manufacturers Association (LCPMA):

- a. Initiation has been made on inaccurate data and hence, the initiation is void ab initio as held in the case of ICI India Ltd. Versus Commissioner of Customs, Calcutta 2003 (151) E.L.T. 336 (Tri. - Del.)
- b. Balance sheet of domestic industry does not show injury. The domestic industry is engaged in trading as well as manufacturing of subject goods. Therefore, the DI itself has been benefited by increased imports.
- c. Increase in imports is due to imports by domestic industry and further the import information of domestic industry has been concealed by the domestic industry.
- d. There has been an increase in production, capacity, capacity utilization and sales of domestic industry. Further, the domestic industry has excess capacity not in concurrence with the demand and hence imports are not causing any losses to domestic industry.
- e. Any loss of domestic industry is due to low capacity utilization of domestic industry which in turn is due to excess built up capacities and imports of domestic industry.
- f. Being the major users of DOP, its members would be the major affected parties in case of safeguard duty imposition, since its members' product does not get any protection.
- g. Thus safeguard duty should not be imposed if it is against Public interest as held in Supreme Court in Food Corpn. of India v. Kamdhenu Cattle Feed Industries ( 1992 Indlaw SC 426), National Buildings Construction Corporation v. S. Raghunathan and Others reported in 1998 (7) SCC 66, United Phosphorous in 1999 for imposition of safeguard duty on white/yellow phosphorous, United Phosphorous v. Director General

(Safeguards), 2000 (118) E.L.T. 326 (Del.), Phosphorous Ltd. Versus Director General (Safeguards) 2000 (118) E.L.T. 310 (S.C.).

- h. There is no unforeseen circumstance which necessitates safeguard duty and further, domestic industry has no adjustment plan.

#### **E. Rejoinder by Domestic industry**

##### On submissions made by Leather Cloth and Plastics Manufacturers Association

- a. Safeguard investigations are on altogether different footings and involve a multi-stage proceeding wherein information is required to be called from respective parties. The Director General is required to initiate for investigations and not investigate for initiation.
- b. The petitioner companies are making a number of different types of plasticizers and are also involved in other trading activities. Balance Sheets of petitioner companies are therefore not relevant for the present purpose.
- c. Imports by domestic industry have not been concealed by the Petitioners, it has been provided in the Petition. Further it is the contention of the Petitioners that imports made by domestic industry should be excluded.
- d. Production, sales, capacity utilization show increase if compared from 2008-09 to 2010-11. It has already been submitted that 2008-09 is an abnormal period due to recession and end to end point comparison alone is not a fair comparison.
- e. The claimed deterioration in profits is not on account of low capacity utilization. In fact, the domestic industry has utilized capacities to some extent by production of other types of plasticizers.
- f. It should be noted that whereas majority producers of Diethyl Phthalate are participating in the present investigations, only one representative of the consumer association has participated in the present safeguard investigations. This alone shows that the possible adverse impact of the proposed safeguard duty shall be minimal. It cannot be ignored that had the impact been significant, a large number of consumers would have raised their concern. The same has however not happened.
- g. It is the confluence of several events which can unite to form the basis of an unforeseen development. The petitioners have provided several events that formed the part of unforeseen development which has led to increase in imports of Diethyl Phthalate in India. These developments were unexpected and clearly constitute 'unforeseen developments'.
- h. It is not necessary that the adjustment plan proposed or invested upon by the domestic industry should start generating results even before the imposition of safeguard duty. The duty is imposed to facilitate the positive adjustment planned/provided by the domestic industry.

##### On submissions made by Government of Korea

- a. The actual data provided for the entire period 2011-12, comparison of which with the annualized data provided earlier would show that there is no significant difference between the annualized data and the actual data.
- b. It is reiterated that the imports of Dioctyl Phthalate have increased in absolute terms as also in relation to production and consumption.
- c. Individual country movements in imports are entirely irrelevant under safeguard investigations.
- d. As a result of decline in demand for the eventual end product in Europe and coupled with significant additions to capacities in China (for Phthalic Anhydride and DOP), procurement of DOP by the Chinese manufacturers declined very steeply.
- e. The domestic industry performance is not linked to safeguard duty on Phthalic Anhydride.

#### **F. Rejoinder by importers/user industry**

##### **Leather Cloth and Plastics Manufacturers Association**

- a. Stake of exporters to Indian market is very small and hence they have not participated. Non participation does not make them supporters of the case.
- b. LCPMA will be highly affected and has been participating from beginning; hence no objection can be raised in this regard.
- c. Data provided by domestic industry has to be verified by Director General as objections have been raised by interested parties and the burden of proof is on the domestic industry.
- d. Domestic industry has not provided transaction wise import data, which would show that imports have been made by domestic industry and interested parties of domestic industry.
- e. There has been no circulation of fresh data as claimed by domestic industry and the plea to ignore 2008-09 data should not be allowed, as it is against the law. Further, as per Carbon black 1998 case, data subsequent to initiation cannot be taken on record.
- f. Surge in imports is due to imports by domestic industry.
- g. Domestic industry has not suffered any injury, in fact domestic industry has profited from imports made by them. Also there is no serious threat of injury to the domestic industry.
- h. Causal link does not exist as imports have been made by domestic industry and are benefiting from the imports.
- i. Duty would be against public interest as there is already an inflationary trend in the market. Calculations shown by domestic industry are without any rational basis.
- j. The domestic industry has no creditable adjustment plan.

##### **Findings by the Director General:**

- I. I have carefully gone through the case records, the replies filed by the domestic producers, user/importers and exporting nations. Submissions made by the various

parties and the issues arising there-from are dealt with at appropriate places in the findings below.

2. Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 deals with imposition of Safeguard Duty on imports into India on non discriminatory basis. Section 8B(1) provides for imposition of Safeguard Duty on the article if the article is being imported into India, in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to the Domestic Industry.
3. The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provide the manner and principles governing investigation.
4. Accordingly, the investigation has been conducted in accordance with the said rules and the final findings are recorded through this notification.

**A. The product under investigation:**

5. The product under investigation is Dioctyl Phthalate (an organic compound) and abbreviated as 'DOP'. It is also known as Bis (2-ethylhexyl) phthalate, commonly abbreviated DEHP. This product is a colorless viscous liquid, soluble in oil, but not in water. It possesses good plasticizing properties. Being produced on a massive scale by many companies, it has acquired many names and acronyms, including BEHP and di-2-ethyl hexyl phthalate. It is widely used as a plasticizer in manufacturing of articles made of PVC. Plastics may contain 1% to 40% of DEHP. It is also used as a hydraulic fluid and as a dielectric fluid in capacitors. DEHP also finds use as a solvent in glow sticks as it has suitable properties and the low cost. It has been used as a plasticizer in medical devices such as intravenous tubing and bags, catheters, nasogastric tubes, dialysis bags and tubing, and blood bags, transfusion tubing and air tubes.
6. Dioctyl Phthalate (DOP) is classified under Customs sub-heading No. 29173920 under the Customs Tariff Act, 1975.
7. The product under investigation is Dioctyl Phthalate (an organic compound) and abbreviated as 'DOP'. It is also known as Bis (2-ethylhexyl) phthalate (di-2-ethylhexyl phthalate, commonly abbreviated DEHP, also an organic compound with the formula C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(C<sub>8</sub>H<sub>17</sub>COO)<sub>2</sub>). The interested parties have not raised any issue with regard to the product under investigation
8. Therefore, domestically produced Dioctyl Phthalate falls under the ambit of like or directly competitive product in all respects to the imported Dioctyl Phthalate and that the domestically produced Dioctyl Phthalate is a like article to the imported Dioctyl Phthalate within the meaning of Rule 2(e) of Safeguard Duty Rules 1997.

**B. Domestic Industry:**

9. Section 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act 1975 defines domestic industry as follows:

*(b) "Domestic industry" mean producers –*

*(i) as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or*

(ii) whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India

10. The application has been filed jointly by M/s KLJ Plasticizers Ltd, Silvassa; M/s N K Polymers & Additives Mfg Co., Daman; M/s Payal Polyplast Ltd, Daman and M/s PCL Oil & Solvents Ltd, Daman for imposition of Safeguard Duty on imports of Dioctyl Phthalate (DOP). The applicants have identified two more producers of Dioctyl Phthalate in India, namely M/s Rachna Plasticizers and M/s Lalitha Chem Industries Pvt. Ltd. However, M/s Lalitha Chem Industries Pvt Ltd is closed as informed by the applicants. The applicants claimed to be major producers on the ground that they account for about 98% of the Indian production. The information on record shows following volume of production of like or directly competitive article in the Country-

Description	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
Applicants	MT	60,242	69,468	77492	74943
Other Indian producers	MT	3515	4753	7218	1878
Total Indian production	MT	63,757	74,221	84,710	76,821
Share of applicants	%	94%	94%	91%	98%

11. Further no claim has been made by the interested parties against the applicants being the domestic industry. Therefore, it is held that the four applicant domestic producers constitute and represent the domestic industry (DI) within the meaning of Section 8B(6)(b)(iii) of the Safeguard Duty Rules 1997.

**C. Period of Investigation (POI):**

12. The Customs Tariff Act, 1975, Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, Agreement on Safeguard and the relevant Article XIX of GATT do not specifically define what the Period of Investigation should be. From several case laws on safeguard measures, it is clear that neither the domestic laws on Safeguard nor Agreement on Safeguard and Article XIX of GATT provides specific guidelines on the period of investigation except the fact that the relevant investigation period should be sufficiently long to allow conclusion to be drawn on increased imports and serious injury.

13. The applicants in the instant case submitted import and injury data from 2009-10 to 2011-12 (upto Dec 2011) contending that year 2008-09 should be ignored and information should be considered from 2009-10 onwards for the present investigations, as the period 2008-09 was an abnormal period where industries both at domestic and international level, not only in the product under consideration, but in a large number of sectors, suffered due to global recession. The Directorate conducted the verification of data pertaining to injury parameters to the extent possible, starting from 2008-09, and the Notice of Initiation was issued with import and injury data from 2008-09 to 2011-12 (upto Dec 2011).

Subsequently, the applicant submitted figure from January to March 2012. The additional information of 3 months was made available to all concerned and kept in the Public File as required under Rule 6(7) of Safeguard Rules 1997.

14. The interested parties claimed that the plea to ignore 2008-09 data should not be allowed as it is against the law. Further, as per Carbon black 1998 case, data subsequent to initiation cannot be taken on record.

15. Considering that the period selected should be sufficiently long to allow conclusions to be drawn regarding existence of increased imports and to neutralize the effect of seasonal variation, data has been considered from F.Y. 2008-09 to 2011-12. In the notice of initiation, import data upto Dec 2011 had been considered. The import data has since been updated till March, 2012. The period has been taken from 2008-09 till 2011-12 for the purpose of the present investigations. As regards the argument that 2008-09 is the abnormal period due to recession and should not be considered, it is clarified that the effect of recession is well taken into consideration while analyzing performance of the domestic industry. Further as regards the argument that new data after initiation cannot be taken on record, it is noted that it is necessary to update the data, for a period subsequent to the period contained in the petition after initiation of investigations, to analyse on actual/absolute basis rather than annualizing the data. The petition/Notice of Initiation contained data for the period up to Dec., 2011. Even interested parties have argued that it would not be appropriate to annualize April-Dec., 2011 data. I therefore consider appropriate and necessary to use data for the period up to March, 2012.

**D. Source of data:**

16. The import data from 2008-09 up to 2010-11 has been taken from DGCIS in consonance with data already taken in Notice of Initiation, and for 2011-12, it has been taken from IBIS. The data on various economic parameters submitted by the domestic industry in their petition till Q3 of 2011-12 has been verified by this directorate to the extent possible and the verified data has been taken into consideration for injury analysis. However, the data upto Q3 of 2011-12 has been updated for the entire year 2011-12, in respect of various economic parameters, as per certified cost statements furnished by the applicants. The IBIS import data for the year 2011-12 has been considered keeping in view the following facts-

(a) DGCIS data for 2011-12 available with the Directorate is not for the complete financial year, in the absence of which it had to be annualized which would not have been appropriate, keeping in view the objections raised by one of the interested party namely Korean Govt against annualization of import data in their post hearing submissions.

(b) IBIS data for 2011-12 is available for the whole year and is also transaction wise, which has also been demanded by one of the interested party namely LCPMA in their post hearing submissions.

(c) Even the domestic industry has also questioned the accuracy of DGCIS data for the year 2011-12 on the ground that it does not reflect complete transaction wise import of Dioetyl Phthalate in the country which is crucial for the injury analysis. They have

submitted transaction wise import data from IBIS for the year 2011-12 along with their letter requesting for considering the same.

**E. Confidentiality of Information submitted**

17. The domestic industry has provided information on confidential basis and sought confidentiality on the information/data submitted. The domestic industry provided non confidential version of all submission including the application for safeguard measure as per the provisions of Safeguard Rules, 1997 and Trade Notice No. SG/TN/1/97 dt. 06.09.1997.
18. Rule 7 of the Safeguards Rules and Article 3.2 of WTO Agreement on Safeguards provide for confidentiality. The applicants is not required to disclose such information which is confidential information of an individual company, disclosure of which can cause serious prejudice to the business interests of the company, which is not in public domain and which the applicants has not disclosed before public at large in the past. Accordingly confidentiality, as prayed for by domestic industry is granted.

**F. Increased Imports:**

19. Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 deals with the power of the Central Government to impose Safeguard Duty and provides as follows:
  1. *"If the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to domestic industry, then, it may, by notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article;"*
20. Further, Rule 2(c) of Customs Tariff ((Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provides as follows
  - (c) *"Increased quantity' includes increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production"*
21. The rules require a determination of whether the product under consideration is imported into India in increased quantities as a basic prerequisite for the application of a safeguard measures. To determine whether imports of the product under consideration have "increased" "in such quantities" for purposes of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of the rate and amount of the increase in imports, in absolute terms and in relation to domestic production and consumption, as has been held by the panel and later confirmed by the Appellate Body in Argentina –Footwear case<sup>1</sup> also.
22. In its evaluation of whether the investigation by the Argentine authorities

<sup>1</sup> *Appellate Body Reports on Argentina — Footwear (EC) WT/DS121/AB/R dated 14 December 1999*

demonstrated the required increase in imports under Articles 2.1 and 4.2(a), the Panel in Argentina-Footwear case<sup>2</sup> stated the following:

... the Agreement requires not just an increase (i.e., any increase) in imports, but an increase in "such...quantities" as to cause or threaten to cause serious injury. The Agreement provides no numerical guidance as to how this is to be judged, nor in our view could it do so. But this does not mean that this requirement is meaningless. To the contrary, we believe that it means that the increase in imports must be judged in its full context, in particular with regard to its "rate and amount" as required by Article 4.2(a). Thus, considering the changes in import levels over the entire period of investigation, as discussed above, seems unavoidable when making a determination of whether there has been an increase in imports "in such quantities" in the sense of Article 2.1. (emphasis added)

23. With regard to the nature of the increase in imports, the Appellate Body in Argentina—Footwear (EC)<sup>3</sup>, in contrast to the Panel, held that the increase in imports must have been recent, sudden, sharp and significant enough to cause or threaten to cause serious injury. Relevant extracts are as follows:

"131. [T]he determination of whether the requirement of imports 'in such increased quantities' is met is not a merely mathematical or technical determination. In other words, it is not enough for an investigation to show simply that imports of the product this year were more than last year—or five years ago. Again, and it bears repeating, not just any increased quantities of imports will suffice. There must be 'such increased quantities' as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry in order to fulfil this requirement for applying a Safeguard measure. And this language in both Article 2.1 of the Agreement on Safeguards and Article XIX:1(a) of the GATT 1994, we believe, requires that the increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause 'serious injury'."

24. The Panel on US — Wheat Gluten<sup>4</sup>, interpreted the phrase "in such increased quantities" as follows:

"8.31 [A]rticle XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 [of the Agreement on Safeguards ("SA")] do not speak only of an 'increase' in imports. Rather, they contain specific requirements with respect to the quantitative and qualitative nature of the 'increase' in imports of the product concerned. Both Article XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 SA require that a product is being imported into the territory of the Member concerned in such increased quantities (absolute or relative to domestic production) as to cause or threaten serious injury. Thus, not just any increase in imports will

<sup>2</sup> Panel Report on Argentina — Footwear (EC) WT/DS121/R dated 25 June 1999

<sup>3</sup> Appellate Body Reports on Argentina — Footwear (EC) WT/DS121/AB/R dated 14

December 1999

<sup>4</sup> Panel Report on US — Wheat Gluten WT/DS166/R 31 July 2000

suffice. Rather, we agree with the Appellate Body's finding in Argentina - Footwear Safeguard that the increase must be sufficiently recent, sudden, sharp and significant, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause serious injury."

25. In US — Line Pipe, the Panel found, in a statement not reviewed by the Appellate Body, that the word "recent" implies a "retrospective analysis"; but that it does not imply an analysis of the conditions immediately preceding the authority's decision nor does it imply that the analysis must focus exclusively on conditions at the very end of the period of investigation. Relevant extracts are as follows:

*"7.024 [W]e note that the Appellate Body in Argentina-Footwear Safeguard found that 'the phrase "is being imported" implies that the increase in imports must have been sudden and recent'. According to Korea, the phrase 'is being imported ... in such increased quantities' refers to 'the period immediately preceding the authority's decision'. The word 'recent' — which was used by the Appellate Body in interpreting the phrase 'is being imported' — is defined as 'not long past; that happened, appeared, began to exist, or existed lately'. In other words, the word 'recent' implies some form of retrospective analysis. It does not imply an analysis of the conditions immediately preceding the authority's decision. Nor does it imply that the analysis must focus exclusively on conditions at the very end of the period of investigation. We consider that an analysis that compares the first semester of 1998 with the first semester of 1999 is not inconsistent with the requirement that the increase in imports be 'recent'."*

26. The analysis of the increased imports of Dioctyl Phthalate has been conducted in the light of the above mentioned evaluations. Dioctyl Phthalate is imported into India from a number of countries, and primarily from Republic of Korea, Malaysia and Taiwan. It has been argued by Leather Cloth and Plastic Manufacturers Association (LCPMA) that domestic producers of the product have themselves imported significant volume of the subject material. Therefore, any analysis of imports should be done excluding such imports made by the domestic industry. The domestic industry has also said that the majority of imports now are either by the importers or consumers and they have no objection if the imports made by the domestic industry are excluded while analyzing increased imports and injury thereof. It is noted that it would be appropriate to analyze the imports after excluding the imports made by the constituents of the domestic industry due to following reasons:

- a. It has been demanded by the opposing interested parties that increase in imports and injury suffered thereof is due to imports made by the domestic industry and therefore in order to analyze the increased imports as also the impact of the imports on the domestic industry, it would be appropriate to examine the trends in imports and consequent change in various economic parameters of the domestic industry after excluding the imports made by the domestic industry from the total imports of the product in question.

- b. The applicants have also contended that imports made by them should be excluded from the gross imports for the purpose of assessment of imports and its impact on the domestic industry.
- c. The impact of the increased imports is required to be determined on the domestic industry. Thus, the imports made by the domestic industry themselves would not, in any case, have had adverse impact on them.
- d. The Rules require the designated authority to examine not only increased imports but also the conditions under which such imports have been made. Section 8B(1) requires the Director General to examine whether the article is imported into India in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry. Thus, the conditions, under which the increased imports have been reported, are also relevant. In the present case, the condition is such that the DI has also imported and thus their import is required to be excluded for a proper analysis.
- e. In any case, the imposition of safeguard duty will be made on a non discriminatory basis and therefore any imports made, whether by domestic industry or otherwise, would be liable for payment of safeguard duty.

27. In view of the above, I have determined increased imports by excluding the imports made by the domestic producers themselves from the total imports of Dioctyl Phthalate for the POI.

28. It is determined that Dioctyl Phthalate has been imported into India (after excluding the imports made by domestic producers) in such increased quantities and under such conditions in absolute terms as well as compared to the domestic production and consumption as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry which is as under:

**(a) Imports:**

Description	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
Total Imports	MT	40,608	35,210	35,346	41,632
Imports made by DI	MT	13,312	13,726	12,798	2,665
Imports(excluding DI imports)	MT	27,296	21,484	22,548	38,967

29. There is a surge in import both in absolute and relative terms. Imports declined from 27,296 MT in 2008-09 to 21,484 MT in 2009-10 and thereafter increased to 22,548 MT (2010-11) and 38,967 MT in 2011-12. It is noted that imports were higher in 2008-09 partly due to recessionary effect in this period and therefore declined in 2009-10. The imports however surged thereafter from 21,484 (2009-10) to 38,967 MT (2011-12), i.e. by 81% which is sharp, sudden and recent.

**(b) Import in relation to production:**

It is seen that during the POI, imports have also increased in relation to total domestic

production, as shown below:

Description	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
<b>Total Indian Production</b>	MT	63,757	74,221	84,710	76,821
<b>Imports(excluding DI imports)</b>	MT	27,296	21,484	22,548	38,967
<b>Imports in relation to production</b>	%	43%	29%	27%	51%

There is a sharp increase of imports to the total production to 51% in 2011-12 from just 27% in 2010-11, which is almost double.

(c) **Import in relation to consumption/demand:**

Description	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
<b>Demand/Consumption</b>	MT	89,708	94,202	101,704	106,093
<b>Imports(excluding DI imports)</b>	MT	27,296	21,484	22,548	38,967
<b>Imports in relation to Demand/consumption</b>	%	30%	23%	22%	37%

30. Similarly, imports also increased its share in the total demand at the cost of sales of domestic industry, causing injury. Between 2009-10 and 2011-12, whereas the consumption increased by 13%, the imports increased by 81%.
31. It is thus seen that Diethyl Phthalate has been imported into India (after excluding the imports made by domestic producers) in such increased quantities in absolute terms as well as compared to the domestic production and consumption as to cause or threatening to cause serious injury to the domestic industry. It is held that the increase in imports shows a rising trend which is significant enough to constitute "increased imports" within the meaning of Section 8B of the Act.
32. As regards the arguments that the Korea's exports dropped to 3382 MT from 11924 MT in the same period in 2011, it is noted that individual country movements in imports are entirely irrelevant under safeguard investigations because cumulative imports from various sources have been considered for surge in imports.

**G. Unforeseen Developments:**

33. It is noted that there is no specific requirement either in Indian Rules or in WTO Agreement on Safeguards on the methodology that should be followed for analyzing unforeseen developments. The Agreement on Safeguard also does not make any prescription with regard to the methodology that should be followed or the parameters that must be met in deciding unforeseen developments. However, it is important to examine the circumstances which have led to increased imports.
34. In Argentina — Footwear (EC) and Korea — Dairy, the Appellate Body held that "any Safeguard measure imposed after the entry into force of the WTO Agreement must comply with the provisions of both the Agreement on Safeguards and Article XIX of the GATT 1994. Article XIX of GATT 1994 states as follows

1. (a) If, as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a contracting party under this Agreement, including tariff concessions, any product is being imported into the territory of that contracting party in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to domestic producers in that territory of like or directly competitive products, the contracting party shall be free, in respect of such product, and to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy such injury, to suspend the obligation in whole or in part or to withdraw or modify the concession.

35. The Appellate Body in Argentina — Footwear (EC case) held that the phrase 'unforeseen developments' means the developments which were unexpected. 'Unforeseen developments' requires that the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been 'unexpected'. The Body in the same case noted a GATT panel report which held that the development must have been unforeseen at the time of tariff negotiation. The Appellate Body in Korea-Dairy case held that unforeseen developments are developments not foreseen or expected when member incurred that obligation.

36. The Appellate Body, in Argentina — Footwear (EC), then held that the requirement of "unforeseen developments" did not establish a separate "condition" for the imposition of safeguard measures, but described a certain set of "circumstances":

37. The panel on US- Steel Safeguards<sup>5</sup> concluded that the confluence of several events can unite to form the basis of an unforeseen development:

"..... The United States argues that the robustness of the US dollar was a development which combined with the other developments, namely, the currency crises in Asia and the former USSR and the continued growth in steel demand in the United States' market as other markets declined, lead to increased imports."

38. I find that the applicants have given a number of reasons for surge in imports, which are summarized below:

a) Setting up of new plants for manufacturing Phthalic Anhydride by China thereby enhancing their Phthalic Anhydride capacities. With the increase in production of Phthalic Anhydride, the production of Dioctyl Phthalate has also increased in China thereby reducing the market opportunity to the third countries foreign producers to export Dioctyl Phthalate to China. Resultantly, these producers are looking for other market for exports of DOP. The decline in exports of Dioctyl Phthalate in China from the major exporting countries can be seen from below:

<sup>5</sup> Para 86 of Korea Dairy case Appellate Body Report Of WTO 36

**Korea Exports of Dioctyl Phthalate**

Period	World	China
2007	2,38,411	1,40,534
2008	2,11,208	1,08,002
2009	2,07,669	86,883
2010	1,85,132	68,172
2011	1,93,678	32,404

Source: Korea Customs

**Malaysia Exports of Dioctyl Phthalate**

Period	World	China
2007	75,954	18,262
2008	62,768	9,969
2009	68,026	16,689
2010	62,344	13,959
2011	37,409	3,224

Source: Malaysia Customs

**Taiwan Exports of Dioctyl Phthalate**

Period	World	China
2007	1,60,843	1,32,649
2008	1,08,075	81,115
2009	1,73,896	1,55,783
2010	84,597	70,212
2011	46,343	19,502

Source: Taiwan Customs

b) **Imports from these countries to India is given below:-**

Period	Korea RP	Taiwan	Malaysia	Total
2008-09	13,424	4,875	11,971	30,270
2009-10	13,967	1,340	15,657	30,964
2010-11	19,223	1,605	6,174	27,002
2011-12	16,798	17,386	6,698	40,882

It may be seen from the table above that Imports to India from Korea RP, Malaysia and Taiwan remained at significant level and cumulatively increased from 30,270 MT to 40,882 MT over the P01 and sharply from 27002 MT in 2010-11 to 40882 MT in 2011-12 i.e. an increase of 34%, which roughly constitutes to about 98 % of the total imports (including that of DI).

c) Moreover, the property bubble-burst in China has impacted most in the current DOP and the downstream PVC market. There has been a reverse trend in the housing,

construction and real estate market in China leading Chinese Government to take strict regulatory measures which is reflected below:

ICIS PRICING (PHTHALIC ANHYDRIDE), 18th November 2011

*Producers said that sentiment among Chinese buyers is still cautious because of fears of a property bubble developing in China, as well as rising inflation in the country.*

ICIS PRICING (PHTHALIC ANHYDRIDE), 28 October 2011

*In China, many polyvinyl chloride (PVC) producers, fearing an upcoming strong correction in the Chinese property market, had stopped stocking up on DOP material. PVC is a commonly used polymer in the construction segment for window panels, door frames, leather sofas and pipes.*

ICIS PRICING (PHTHALIC ANHYDRIDE), 23 December, 2011

*Regional producers and traders said that buyers were still cautious about committing to bulk purchases, as they were concerned about the health of their domestic real estate market.*

*Local media in China reported that government-sponsored land auctions in cities nationwide have slowed in recent months, reflecting shrinking consumer.*

ICIS PRICING (PHTHALIC ANHYDRIDE), 30th December 2011

*Buyers, however, are concerned with the health of China's property market. The country's once red-hot property market cooled off considerably after a tough round of tightening policies was passed by the Chinese government from April.*

*China will maintain its regulation policies on the property market next year to return housing prices to a reasonable level, according to decisions made at the country's central economic work conference earlier this month.*

d) Whereas initially China, which was a net importer of DOP and Phthalic Anhydride, it started exporting to the Eurozone and other Countries given its excessive capacity and nil demand in domestic market post-Olympics. But in the light of Eurozone debt crisis the demand of DOP in those markets is unstable, leading DOP and upstream Phthalic Anhydride producers to dump their inventories at whatever price available.

ICIS PRICING (PHTHALIC ANHYDRIDE), 16th December 2011

*This means that PA producers could be in for a rough ride moving into 2012, as PA is one of the feedstock's used in the production of diethyl phthalate (DOP). DOP is used heavily in the production of construction materials and consumer goods.*

*The euro zone is a large importer of these products from both China and southeast.*

*Regional traders, however, cautioned that the price rally could be short-lived, because of global economic uncertainty and the euro zone financial crisis.*

**ICIS PRICING (PHTHALIC ANHYDRIDE), 23 December, 2011**

*Traders and buyers said that they were also concerned about the continuing euro zone sovereign debt crisis. The euro zone is a large importer of construction materials and consumer goods from China.*

**ICIS PRICING (PHTHALIC ANHYDRIDE), 30th December 2011**

*Meanwhile, the sovereign debt crisis in the euro zone remains unresolved and buying interest from the construction industry has plummeted as a mood of austerity prevails in the region.*

39. Having regard to the information on record and submissions made by the interested parties, it is observed that the imports of product under consideration increased for a number of reasons. Setting up of new plants of phthalic anhydride in China which resulted in increase in production of Phthalic Anhydride, the production of Diocyl Phthalate has also increased in China thereby reducing the market opportunity to the third countries foreign producers to export Diocyl Phthalate to China. Exporters from Korea and Taiwan were compelled to search for the growing market for their product and India being the most viable choice was targeted, leading to increased imports in India. All these factors taken together form the unforeseen reasons for the increase in imports of DOP. Therefore, I hold the rise in import of Diocyl Phthalate from Korea and Taiwan to be an unforeseen development resulting in increase in imports causing serious injury and threat of serious injury to the domestic industry.

**H. Serious Injury and Threat of Serious Injury:**

40. "Serious injury" means an injury causing overall impairment in the performance of the domestic industry; and "threat of serious injury" means a clear and imminent danger of serious injury.

41. The Article 4.2(a) of the Agreement on Safeguard and Annexure to Rule 8 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 requires that certain listed factors as well as other relevant factors must be evaluated to determine serious injury or threat of serious injury. However, these provisions do not specify what such an evaluation must demonstrate. Any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining". In one case, for example, "overall impairment" of the industry. Thus, in addition to a technical examination of all

the listed factors and any other relevant factors, it is essential that the overall position of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

42. In *Argentina — Footwear (EC)*<sup>6</sup>, the Appellate Body discussed the relationship between the definition of "serious injury" in Article 4.1(a) and the requirement of an evaluation of "all relevant factors" in Article 4.2(a):

"[I]t is only when the overall position of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on a situation of that industry, that it can be determined whether there is 'a significant overall impairment' in the position of that industry. Although Article 4.2(a) technically requires that certain listed factors must be evaluated, and that all other relevant factors must be evaluated, that provision does not specify what such an evaluation must demonstrate. Obviously, any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is 'declining'. In one case, for example, there may be significant declines in sales, employment and productivity that will show 'significant overall impairment' in the position of the industry, and therefore will justify a finding of serious injury. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate 'significant overall impairment' of the industry. Thus, in addition to a technical examination of whether the competent authorities in a particular case have evaluated all the listed factors and any other relevant factors, we believe that it is essential for a panel to take the definition of 'serious injury' in Article 4.1(a) of the Agreement on Safeguards into account in its review of any determination of 'serious injury'."

43. The Panel on US — *Wheat Gluten*<sup>7</sup>, in a finding upheld by the Appellate Body, elaborated on the meaning of the term "serious injury":

"[A] determination as to the existence of such 'significant overall impairment' can be made only on the basis of an evaluation of the overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

[W]e do not consider that a negative trend in every single factor examined is necessary in order for an industry to be in a position of significant overall impairment. Rather, it is the totality of the trends, and their interaction, which must be taken into account in a serious injury determination. Thus, such upturns in a number of factors would not necessarily preclude a determination of serious injury. It

<sup>6</sup> Appellate Body Reports on *Argentina — Footwear (EC)* WT/DS121/AB/R dated 14 December 1999

<sup>7</sup> Panel Report on US — *Wheat Gluten* WT/DS166/R 31 July 2000

*is for the investigating authorities to assess and weigh the evidence before them, and to give an adequate, reasoned and reasonable explanation of how the facts support the determination made."*

44. Accordingly, in analyzing serious injury or threat of serious injury all factors, which are mentioned in the rules as well as other factors which are relevant for determination of serious injury or threat of serious injury, have been considered. No single factor has been considered as dispositive. All relevant factors within the context of the relevant business cycle and conditions which are relevant to the affected industry have been considered. The determination of serious injury or threat of serious injury is based on evaluation of the overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

45. It is held that the increased imports of Diethyl Phthalate have caused and are threatening to cause serious injury to the domestic producers of Diethyl Phthalate as indicated by the following factors.

**a. Demand/consumption:**

46. Demand or apparent consumption of the product in India has been determined as the sum of sales of Domestic Industry and imports from all sources (excluding imports made by domestic industry). It is noted that the demand of Diethyl Phthalate has shown a positive trend throughout the period.

Year	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
Sales of Domestic Industry	MT	58,880	67,959	72,035	65,221
Sales of other producers	MT	3,532	4,759	7,121	1,905
Imports Volume	MT	27,296	21,484	22,548	38,967
Total Demand/Consumption	MT	89,708	94,202	101,704	106,093

47. It is seen that with the increase in demand, the sales of domestic industry have only increased by 11% in 2011-12 since the base year but the Imports have increased by 43% in 2011-12 since the base year.

**b. Market Share:**

48. It is seen from the table below that the market share of the domestic industry in the total consumption has declined.

Market share (in Demand)	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
Domestic Industry	MT	66%	72%	71%	61%
Producers (other than DI)	MT	4%	5%	7%	2%
Import	MT	30%	23%	22%	37%

The market share of the domestic industry increased from 66% (2008-09) to 72% (2009-10) and thereafter declined to 71% (2010-11) and further to 61% (2011-12). It is noted that the market share of imports was high and consequently market share of the domestic industry

was low in 2008-09 due to recessionary effect in this period. Market share of the domestic industry increased in 2009-10. The same however declined, thereafter, significantly.

**c. Production:**

49. The production has been determined on the basis of production reported by the Domestic Industry in its excise records. The statistics relating to production pertaining to the domestic industry is shown below.

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
Total Capacity	MT	155,750	155,750	155,750	190,750
Production	MT	60,242	69,468	77,492	74,943

50. It is seen that the production of the domestic industry was increasing from 60242 MT (2008-09) to 69468 MT (2009-10) and then to 77492 MT (2010-11). The production however thereafter declined to 74943 MT in 2011-12. Given that the domestic industry further enhanced its capacity in 2011-12, the decline in production despite increase in capacity is quite significant and is clearly adverse situation.

**d. Domestic sale:**

51. The sale of the domestic industry has been determined on the basis of goods cleared by the Domestic Industry from their factory premises for domestic market, as reported in their excise records. The table below contains sales by domestic industry and total export.

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
Sales Volume - Domestic	MT	58,880	67,959	72,035	65,221
Sales Volume - Exports	MT	1,326	1,892	4,274	10,023
Sales Volume - Total	MT	60,206	69,851	76,309	75,244

52. It is seen that the domestic sales grew from 58,880 MT (2008-09) to 67,959 MT (2009-10) and were 72,035 MT in 2010-11. The domestic sales however, declined thereafter to 65,221 MT in 2011-12. The domestic sales of the domestic industry have declined in the most recent period. Even rise in exports did not improve the condition in 2011-12 when DI incurred losses and inventory kept piling up.

**e. Capacity Utilization:**

53. Capacity utilization of the domestic industry was as follows –

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
Plant Capacity	MT	155,750	155,750	155,750	190,750
Production of PUC	MT	60,242	69,468	77,492	74,943
Capacity utilization	%	39%	45%	50%	39%

54. It is seen that the capacity utilization of the domestic industry was increasing from 39% (2008-09) to 45% (2009-10) and then to 50% (2010-11). The capacity utilization however thereafter declined to 39% in 2011-12.

55. Given that the domestic industry enhanced its capacity in 2011-12, it was considered whether the decline in capacity utilization was due to increase in capacity. It is noted that had the domestic industry not enhanced capacity, its utilization in 2011-12 would have been 48%. Thus, capacity utilization would have shown decline even if the domestic industry would not have enhanced capacity.

56. It is argued by the interested parties that the domestic industry has excessive capacities. The domestic industry clarified in this regard that it has capacities which are being used for production of other products as well and the domestic industry on its part made efforts to utilize the plants and hence the low utilization given above does not mean inefficiencies of the domestic industry or high fixed costs of the domestic industry.

**f. Inventories:**

57. As the market share of the domestic industry is decreasing and that of imports is increasing, the domestic industry was unable to increase its sales volume in proportion to increase in demand and had to face the problems of accumulated inventories. The levels of average inventories declined in 2009-10 to 823 MT but thereafter increased to 1,223 MT in 2010-11 and 1744 MT in 2011-12.

Year	Index	Average Inventory(MT)
2008-09	100	1066
2009-10	77	823
2010-11	115	1223
2011-12	163	1744

**g. Employment and productivity:**

There is no significant change in the level of employment and in productivity over the injury period. It has shown normal growth over the period. It is observed that these parameters are dependent on a number of other parameters and not reflective of impact of imports on the domestic industry.

**h. Price undercutting, suppression/depression:**

58. It is seen that the landed price of imports is below the selling price of the domestic industry. The imports are available at prices lower than the selling price of domestic industry making it attractive for consumers to switch over to imports. Due to low priced imports, domestic industry is facing decline in production, capacity utilization,

profits and return on investment.

59. The trend in cost of production and selling price is also examined. It is seen that whereas both the cost of production and selling price increased, the increase in selling price is less than the increase in cost of production.

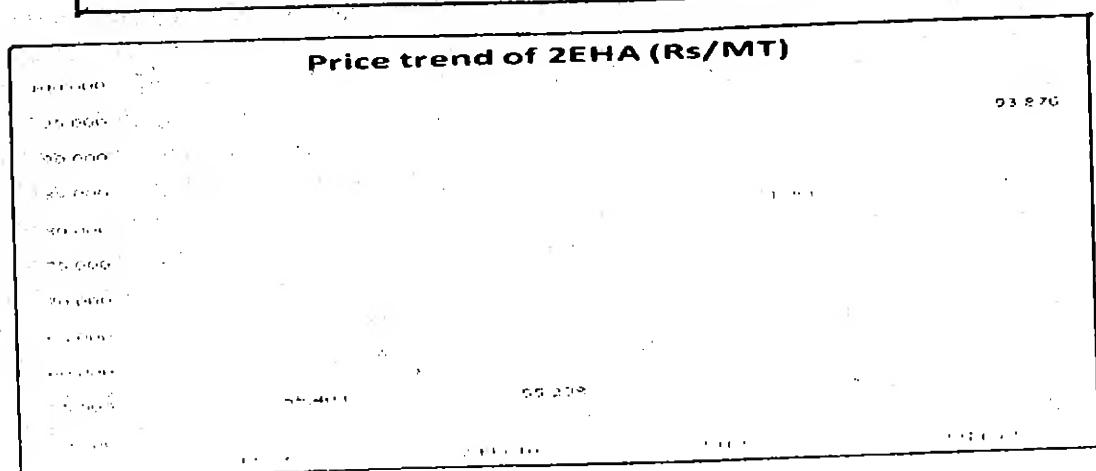
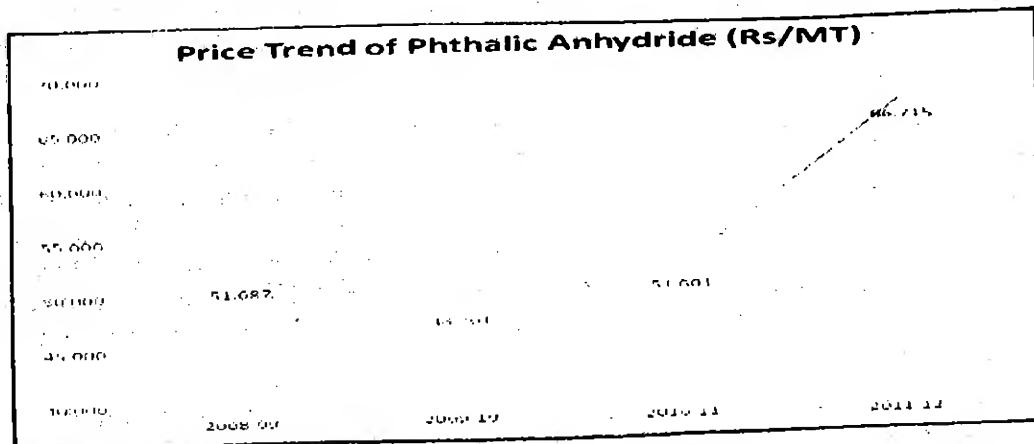
Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
Cost of Production	Indexed	100	87	113	127
Selling price	Indexed	100	93	120	126

(Source : Domestic Industry)

60. The reasons for increase in cost of production were also examined. It is noted that the major raw material for manufacture of Dioctyl Phthalate is Phthalic Anhydride(PAN) and 2 EHA. The price movement in Phthalic Anhydride & 2 EHA prices is as follows:

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
Cost of Production	Indexed	100	87	113	127
Price of Phthalic Anhydride	Indexed	100	94	100	129
Prices of 2EHA	Indexed	100	100	148	169
Total Raw Material Cost	Indexed	100	98	131	155

(Source : Domestic Industry)



61. It is seen that the cost of production of the domestic industry has moved in tandem with the price of major raw material throughout the injury period. It is therefore concluded that the increase in cost of production is due to increase in raw material prices.

**i. Profit & Loss:**

62. The Domestic Industry has reported profit before tax, duly certified by a practicing Chartered Accountant. The profitability of the domestic industry has steeply deteriorated to such a situation that the domestic industry is now suffering financial losses. This is evident from the table below:-

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
Profit/(Loss)	Rs./Lacs	(****)	****	****	(****)
Profit/Loss (Indexed)	%	(100)	404	509	(210)

(Source : Certified cost statements of the four companies constituting domestic industry)

63. It is seen that the domestic industry suffered losses during 2008-09, which the domestic industry contended was due to recession. The domestic industry was however thereafter able to earn profits in 2009-10, extent of which increased till 2010-11. The domestic industry however suffered significant financial losses once again in 2011-12 clearly showing the effect of increased imports.

64. As regards the argument of the interested parties that the balance sheet of the domestic industry does not show injury, it is noted that constituents of domestic industry are making a number of different types of plasticizers and are also involved in other trading activities. The annual report does not provide performance dedicated for Dioctyl Phthalate and therefore annual report cannot be relied upon. Further Dioctyl Phthalate constitutes 50-60% of the total turnover of the domestic industry over the period considered and therefore the balance sheet, which provides for the overall performance of the domestic industry, cannot be relied upon for the Dioctyl Phthalate performance.

**65. Conclusion regarding serious injury** –The imports of the product under consideration have increased significantly in absolute terms and in relation to production and consumption in India. It is noted that the imports volume was high in 2008-09, which the domestic industry contended, was due to global recessionary effect. The volume of imports both in absolute terms and in relation to production and consumption declined in 2009-10 after the recessionary effect was subsided. However, the imports surged thereafter significantly both in absolute terms and in relation to production and consumption in India. As a result of significant surge in imports, the domestic industry has suffered serious injury. Performance of the domestic industry improved upto 2010-11 in respect of production, capacity utilization, domestic sales and profits. Production, capacity utilization, domestic sales, profits however declined significantly in 2011-12. Market share of the domestic industry improved in 2009-10 and declined thereafter significantly. Inventories with the domestic industry declined in 2009-10 and increased thereafter. Thus, evaluation of the overall position of the domestic industry in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of the

domestic industry, shows 'a significant overall impairment'. It is thus concluded that domestic industry has suffered serious injury as a result of increased imports of the product under consideration.

**j. Threat of serious injury**

66. Section 8B subsection 6(d) of Customs Tariff Act provides as follows:

*"threat of serious injury" means a clear and imminent danger of serious injury.*

67. The rules provides as follows :-

*"In the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a domestic industry, the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment."*

68. The Panel on US — Lamb considered that a focus on the recent data available pertaining to the end of an investigation period was logical in view of the future-oriented nature of a threat of serious injury analysis. The relevant extracts are as follows:

*"In our view, due to the future-oriented nature of a threat analysis, it would seem logical that occurrences at the beginning of an investigation period are less relevant than those at the end of that period. While the SG Agreement does not specify the appropriate duration of the time-period to be considered in an investigation, the Panel and Appellate Body in Argentina — Footwear both considered this issue to some extent. Both concluded that (for an actual serious injury finding) the most recent data were clearly the most relevant. In particular, the Appellate Body stated that 'the relevant investigation period should not only end in the very recent past, the investigation period should be the recent past'.*

*Given that a threat of serious injury pertains to imminent significant overall impairment, i.e., an event to take place in the immediate future, the same principle should hold true a fortiori for threat determinations compared with present serious injury determinations. This supports the view that the USITC was correct to focus on the most recent data available from the end of the investigation period. We also consider that data from 1997 and interim-1998 cover an adequate and reasonable time-period if complemented by projections extrapolating existing trends into the imminent future so as to ensure the prospective analysis which a threat determination requires.*

*Therefore, we consider that, by basing its determination on events at the end of the investigation period (i.e., one year and nine months) rather than over the course of the entire investigation period, the USITC analysed sufficiently recent data for making a valid evaluation of whether significant overall impairment was "imminent" in the near future. By the same token, we also consider that, by basing its determination at all on data about events from the recent past, rather than relying exclusively on projections for the various industry indicators into the future, the USITC made its threat determination on the basis of objective and quantifiable facts, and not merely on allegation, conjecture or remote possibility'*

69. The Panel Report on US — Lamb, in a finding subsequently not reviewed by the Appellate Body, which addressed the question whether once imports have increased to already cause some degree of injury, there is no requirement of additional increased imports in order to legitimately determine the existence of a threat of serious injury. The relevant extracts are as follows:

*"The complainants further claim that the US reference to projections of future increases in imports in defending its threat analysis amounts to equating a 'threat of increased imports' with a 'threat of serious injury', which the Argentina — Footwear panel found not to be permissible....*

*We agree in general with the complainants' argument that a threat of increased imports as such cannot be equated with threat of serious injury. However, in our view, this is not what the USITC has done in this case. Moreover, we also deem it possible that imports continuing on an elevated level for a longer period without further increasing at the end of the investigation period may, if unchecked, go on to cause serious injury (i.e., may threaten to cause serious injury). That is, if increased imports at a certain point in time cause less than serious injury, it is not necessarily true that a threat of serious injury can only be caused by a further increase, i.e., additional increased imports. In our view, in the particular circumstances of a case, a continuation of imports at an already recently increased level may suffice to cause such threat.*

70. There is a threat of serious injury to the DI due to surge in imports & due to excessive capacity creation by China to meet its short-lived demand for DOP and other downstream products like PVC.

Source: ICIS PRICING (PHTHALIC ANHYDRIDE), 28 October 2011

*China's Continental Petrochemicals (Zhuhai) has resumed the construction work at its new integrated petrochemicals facility at Zhuhai in China, a source close to the company said on Thursday. The complex will house a 120,000 tonne/year DOP plant and an 80,000 tonne/year PA plant.*

*Taiwan's UPC Technology Corp is aiming to bring on stream its new petrochemical complex at Liaoyang in China's Liaoning province by mid-July 2013, a company*

source said on Thursday, UPC will start building the complex early next year said the source. The complex will comprise a 140,000 tonne/year PA plant and a 240,000 tonne/year DOP plant.

Source: ICIS PRICING (PHTHALIC ANHYDRIDE), 2nd December 2011

*Taiwan's Nan Ya Plastics is aiming to bring its total PA operating rate to 100% of capacity by the middle of December, as the company is expecting PA demand from China and southeast Asia to pick up by the end of the year, a company source said on Friday.*

*The source added that Nan Ya's demand for PA will increase when it restarts its downstream 400,000 tonne/year diethyl phthalate (DOP) plant at the same site on 5 December.*

71. Furthermore, a significant impact on DOP market has been of floods in Thailand which grappled the buying trends in the country at zero level. This resulted in diversion of Chinese inventories to other viable markets. This situation persists in light of already existing capacities with Korean and Taiwanese producers which once were chief exporters of DOP to China. In fact, one Taiwanese producer is in process of starting up its under-construction facility in July 2013, comprising a 140,000 tonne/year Phthalic Anhydride plant and a 240,000 tonne/year DOP plant.

ICIS PRICING (PHTHALIC ANHYDRIDE), 9th December 2011

*Buyers in Thailand are buying only on a need-to basis, as most of their plants are not operating at full capacity.*

ICIS PRICING (PHTHALIC ANHYDRIDE), 16th December 2011

*In Thailand, buying interest remains slow as the country is still grappling with clearing floodwaters from their factories.*

72. The imports are entering the Indian market in increased quantities in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. Significant price difference between the domestic and imported product establishes the adverse price effect of increased imports on Domestic Industry. Considering the net selling price of the domestic industry for the subject goods, the price difference between domestic and imports is significantly high and is likely to remain positive making the imports lucrative and threatening injury to the domestic industry.

#### **k. Other Factors of Injury:**

73. Para (2) of Annexure to Rule 8 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 lays down that The determination referred to in subparagraph (1) shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of

objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the article concerned and serious injury or threat thereof. When factors other than increased import are causing "serious injury" to the Domestic Industry at the same time, such "serious injury" shall not be attributed to increased imports. As such, the possible other factors that may be attributed to the serious injury to Domestic Industry have been examined.

74. Followings are relevant in this regard –

- a) Demand of the product: While overall demand has increased, volume of imports remained significant. In fact, it is noted whereas the market share of the domestic industry and domestic producers as a whole declined, that of imports increased. It is thus clearly seen that the increased imports have taken away higher share of the demand.
- b) Changes in the patterns of consumption: The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Changes in the pattern of consumption could not have contributed to the injury to the domestic industry.
- c) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers: There is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.
- d) Export performance: Applicants have exported small volumes of the product under consideration. However, the claimed injury to the domestic industry is on account of domestic operations. Applicants have provided costing and injury information for domestic operation. Claimed injury to domestic industry cannot be attributed to exports.
- e) Developments in technology: Technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.

75. It is thus noted that possible other factors have not caused injury to the domestic industry.

#### **1. Causal Link between Increased Import and Serious injury or Threat of Serious injury:**

76. A comprehensive evaluation of parameters as above demonstrates that serious injury and threat of serious injury is being caused by increased imports. For the purpose of determining causation, all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of the industry have been evaluated. In the instant case, the imports are available at prices lower than the selling price of Domestic Industry. The consumers are increasingly switching over to imports due to which the Domestic Industry is faced with losing sales and rising inventory. The production, capacity utilization, profits, return on investment, all declined due to increased imports. The imports are undercutting the prices of the Domestic Industry. Consequently, the Domestic Industry has suffered decline in profits and return on investment. This is in a situation when the total available capacity of the DI is more than the domestic demand/consumption. It is thus evident that serious injury to the Domestic Industry

has been caused by the increased imports.

**J. Public Interest:**

77. Article 3 of the Agreement on Safeguards states as follows:

*1. A Member may apply a Safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT 1994. This investigation shall include reasonable public notice to all interested parties and public hearings or other appropriate means in which importers, exporters and other interested parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, *inter alia*, as to whether or not the application of a Safeguard measure would be in the public interest. The competent authorities shall publish a report setting forth their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law.*

78. The imposition of safeguard duty can affect different players differently and the impacts may not always be most suitable for different economic players when they have competing interests. Therefore interests of various economic player groups have been analyzed based on the available information.

79. LCPMA submitted as follows:

- a) Being the major users of DOP, LCPMA members would be the major affected parties in case of imposition of safeguard duty since their product does not get any protection. Thus safeguard duty should not be imposed if it is against public interest.
- b) LCPMA members are also domestic industry and also need a fair play to compete with imports of their finished goods. There is no extra protection for their products. The leading foreign leather cloth producers are keen to export leather cloth to India.
- c) Since all state actions are taken in larger public interest, it is imperative for the government authorities to examine public interest issue.

80. The domestic industry submitted as follows:

- a) The Plastiziers consumer industry is such that it can and does pass over its cost increases to the downstream products. Further the impact of say 20% safeguard duty on its 3 major users is minimal, as the impact of the same on Leather Cloth is 0.29%, on Copper cable is 0.02% and on PVC flexible pipe is 0.43% which is almost negligible.
- b) DOP has nil customs duty protection. Two major raw materials namely Phthalic Anhydride and 2EHA used in the production of the product under consideration have the same level of customs duty. However, these two have 2.5% duty protection respectively.
- c) In the past decade a number of producers have already shut down their operations. Moreover, if the injury to the domestic industry continues, it may lead to the closure of the remaining domestic producers, as a result of which, 'DOP' an important

chemical would not be manufactured in the Country thereby leaving the users of the 'DOP' wholly dependent on the imports.

81. It is seen that the selling price of the domestic industry is significantly lower than the cost of sales. Considering the present profitability of the DOP industry, non levy of safeguard duty can lead to closure of DOP industry. In any case, the producers of Dioctyl Phthalate does not have any duty protection which coupled with the fact that the many producers in the past have closed down their operation and the minimal impact of safeguard duty on consumers, it noted that imposition of safeguard duty would be in public interest.

82. The imposition of safeguard duty would be in public interest as it will not only prevent injury to the domestic industry but also would help in checking further decline of the domestic industry.

83. The domestic industry has quantified the impact of 20% safeguard duty on eventual downstream products. It is found that the 20% increase in price on account of safeguard duty, if fully passed onto the eventual end product (assuming that the domestic industry increases the prices by 20%) would have minimal impact on the eventual end products, as is seen from the following

- a. Leather Cloth 0.29%.
- b. Copper cable 0.02%
- c. PVC flexible pipe is 0.43%.

84. The above claim of domestic industry has not been disputed by the consumer association or other interested parties present at the time of oral hearing. Nor the written submissions filed by any interested party contain any other quantified claim to the contrary. It is concluded that even if the prices are increased by 20%, the impact of the same on the eventual end product would not be significantly adverse. The imposition of safeguard duty will not result in significant increase in the prices of eventual end products.

85. In the light of the facts on record, it is concluded that imposition of safeguard duty would be in public interest and the interests of end users would not be very adversely impacted.

#### **K. Adjustment Plan:**

86. It has been argued by opposing interested parties that the domestic industry has not submitted viable adjustment plan to meet the international competition. The applicants submitted adjustment plan with the application and subsequent written submissions.

87. The Rule 5(2) of Safeguard Rules 1997 requires submission of a statement on "*efforts being taken or planned to be taken or both to make positive adjustment to import competition*". The WTO Agreement on Safeguard provides that a member shall apply safeguard measure only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and facilitate adjustment.

88. The purpose of definitive safeguard measure is to provide the domestic producers with a limited period of time in which to restructure so as to more effectively compete with the

imports. Section 8B (4) of Customs Tariff Act 1975 and Rule 16(2) of Safeguard Rules 1997 prohibits any possible extension of measure if there is no evidence that the domestic producers are adjusting.

89. Following are the adjustments plan provided by the domestic industry essentially comprising of the following:

- d. Batch process to continuous process
- e. Automation of plants
- f. Waste Recovery
- g. Reduction in energy cost
- h. Stringent monitoring of the plant using IT
- i. Reduction in administrative expenses
- j. Effective inventory management
- k. Power saving by modernizing electrical equipments
- l. Use of better manufacturing practices
- m. Improvement in management practices

90. The restructuring plan submitted by the domestic industry focuses on cost reduction and optimum utilization of existing production capacity. It is noted that the adjustment plan of domestic industry is reasonable and feasible and viable which is likely to be implemented.

91. It is further noted that Domestic Industry has already started its efforts towards its cost reduction in terms of energy cost, administration overheads and other conversion cost etc, which is evident from the table below:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12
Cost of Production	Indexed	100	130	146
Total Raw Material Cost	Indexed	100	134	159
Overhead /conversion cost	Indexed	100	111	89

92. It is evident from the table above that Overhead cost of the Domestic Industry has declined in the recent period viz 2011-12 despite increase in raw material cost. This shows that industry has taken efforts to improve efficiency in operating norms in the recent period.

#### L. Developing Nations:

93. The percentages of imports from developing nations have also been examined. Except Malaysia who constitutes 16.72% of total imports in India during FY 2010-11 and FY 2011-12, other developing nations individually and collectively have less than 3% and 9% share respectively of total imports in India. Therefore, imports of product under consideration originating from developing nations except Malaysia may not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.

#### M. Conclusion:

94. In view of the findings above, it is concluded that increased imports of Dioctyl Phthalate into India have caused or threatened to cause serious injury to the domestic producers of Dioctyl Phthalate and it will be in the public interest to impose safeguard duty on imports of Dioctyl Phthalate into India, in terms of Rule 12 of the Customs Tariff

(Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules 1997. The period is considered to be the minimum requirement to protect the interest of domestic industry. Further, the calculated safeguard duty has been moderated downward to allow imports to maintain competition in domestic market in the interest of end users and consumers. The domestic producers have claimed a certain amount of profit on the basis of expected return on capital employed etc. which is considered to be on the higher side and, therefore, a lower amount of profit (confidential) based on the weighted average cost of production has been considered appropriate and allowed. Thus, on the basis of the above findings it is seen that

- a. Imports of the product under consideration have increased over the injury period in absolute terms with a sharp increase in imports in the recent period.
- b. Increased imports of DOP (Dioctyl Phthalate) from various countries have caused and threatened to cause serious injury to the domestic industry/producers of DOP; and
- c. It has been established that injury to various economic parameters of the domestic industry like production, sale, inventory etc. has been caused by the increased imports of DOP; and
- d. It will be in the public interest to impose safeguard duty on imports of DOP from all countries, except originating from developing nations except Malaysia in terms of proviso to Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.

**N. Recommendation:**

95. In terms of Rule 12 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules 1997, after considering the average cost of production of Dioctyl Phthalate by the domestic producers, after allowing a reasonable return on capital employed, a Safeguard Duty on all import of Dioctyl phthalate, an organic compound and abbreviated as DOP falling under Chapter heading 29173920 under the Custom Tariff Act '75 and also known commonly as Bis (2-ethylhexyl) phthalate(di-2-ethylhexyl) phthalate, commonly abbreviated DEHP, also an organic compound with the formula  $C_{6}H_{4}(C_{8}H_{17}COO)_2$  is hereby recommended for imposition in the following manner:

Period	Rate of Safeguard duty
First year	15%
Second year	10%

Recommendation for levying of the aforementioned safeguard duty is considered to be the minimum required to protect the interest of domestic industry, to be imposed on imports of such goods on a non discriminatory basis. However, as the imports from developing nations except Malaysia do not exceed 3% individually and 9% collectively, the import of product under consideration originating from developing nations except Malaysia may not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.

[F. No. D-22011/13/2011/Part A]

INDRANI DUTT MAJUMDER, Director General